

## निजीकरण और धन सृजन

मुक्त उद्यम ने मनुष्य की रचनात्मकता और अर्जनशीलता की तीव्र इच्छाओं को इस रूप में अभिव्यक्त करने के लिए सक्षम बना दिया है जो समाज के सभी लोगों को लाभान्वित करता है। अब मुक्त उद्यम को संघर्ष करने दें, अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए जो स्वतंत्रता में आस्था रखते हैं।

- मार्गरेट थैचर

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में सामरिक विनिवेश के हाल के अनुमोदन ने बीपीसीएल के शेयरधारकों की इक्विटी के मूल्य में 33,000 करोड़ रु. की वृद्धि में मुख्य भूमिका निभाई। यह बीपीसीएल की दक्षता में अहम सुधारों से प्रत्याशित लाभ सहित कंपनी के कुल मूल्य में वृद्धि दर्शाता है, जब इसकी एचपीसीएल से तुलना की जाती है, जो सरकार के नियंत्रणाधीन बनी रहेगी। इसलिए यह अध्याय भारतीय परिप्रेक्ष्य में निजीकरण से सहित दक्षता लाभ की जांच करने का प्रयास करता है। यह 11 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) के पूर्व-पश्चात निष्पादन का विश्लेषण करता है, जिनमें 1999-2000 से 2003-04 तक कार्यनीतिक विनिवेश किया गया है। अंतर में अंतर कार्यप्रणाली का उपयोग करते हुए सावधानीपूर्वक तुलना करने के लिए इन सीपीएसई की तुलना समान उद्योग समूह में समकक्ष कंपनियों से की गई है। हमारा विश्लेषण दर्शाता है कि निजीकृत सीपीएसई की निवल संपत्ति, शुद्ध लाभ और परिसंपत्तियों पर लाभ निजीकरण के पश्चात अवधि में औसतन काफी बढ़ा है। इस अवधि के दौरान इन सीपीएसई ने अपनी समकक्ष कंपनियों से औसतन कहीं बेहतर निष्पादन भी किया है। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि RoA समकक्ष कंपनियों को पीछे छोड़ते हुए नकारात्मक से सकारात्मक में परिवर्तित हुआ है, जो यह दर्शाता है कि निजीकृत सीपीएसई समान संसाधनों से अधिक धन जुटाने में सफल रहे हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता में भी वृद्धि हुई है, चूंकि निजीकरण की अवधि के पश्चात प्रति कर्मचारी सभी परिवर्तीकारकों जैसे प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ, प्रति कर्मचारी सकल राजस्व और प्रति कर्मचारी निवल संपत्ति में वृद्धि हुई है। निष्पादन में यह सुधार प्रत्येक सीपीएसई में व्यक्तिगत रूप से भी लागू होता है। हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से दावे के साथ कहता है कि सीपीएसई की कार्यनीतिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश इन उपक्रमों को निवल संपत्ति, लाभप्रदता, विक्रय वृद्धि, दक्षता और अपने हितधारकों को लाभ देने की शर्तों पर बेहतर निष्पादन द्वारा प्रदर्शित संपत्ति सृजन के सामर्थ्य के द्वार खोल देता है। इसलिए यह अध्ययन सामरिक बिक्री के मार्ग के माध्यम से आक्रमक विनिवेश के विषय को बल देता है।

9.1 नवंबर, 2019 में भारत ने एक दशक से अधिक समय में अपना सबसे बड़ा निजीकरण अभियान शुरू किया है। चुनिंदा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (सीपीएसई) में भारत सरकार के प्रदत्त पूंजी भाग को 51% से कम करने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दे दी गई है। चुनिंदा सीपीएसई में से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

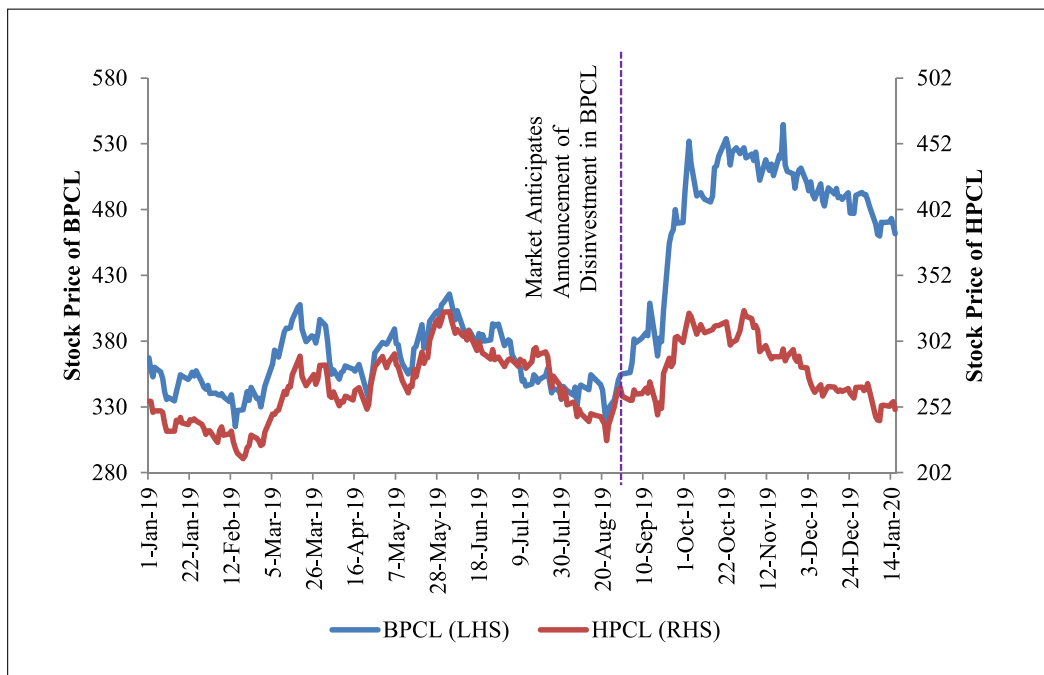
(बीपीसीएल) में सरकार की 53.29% शेयरधारिता के सामरिक विनिवेश को मंजूरी दे दी गई। आकृति 1 में अपनी समकक्षी हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तुलना में बीपीसीएल का शेयर मूल्य दर्शाया गया है। हम सितंबर 2019 से बीपीसीएल और बीएचसीएल के मूल्यों में अंतर पर अपना ध्यान केन्द्रित

करेंगे जब बीपीसीएल के निजीकरण की खबर पहली बार सामने आई थी।<sup>1</sup> बीपीसीएल और एचपीसीएल की तुलना यह सुनिश्चित करती है कि शेयर बाजार में या तेल उद्योग में कोई व्यापक उठापटक को दूर किया जा सके। हम आकृति 1 में यह देखते हैं कि एचपीसीएल ओर बीपीसीएल के शेयर मूल्यों की सितंबर तक एक समान गति थी। तथापि, बीपीसीएल के विनिवेश की घोषणा के पश्चात उनके शेयर मूल्यों में विचलन आरंभ हुआ। समान अवधि में बीपीसीएल के शेयर मूल्य में वृद्धि की जब एचपीसीएल के मूल्य में परिवर्तन से करते हैं तो बीपीसीएल के शेयरधारिता इक्विटी के मूल्य

में लगभग 38000 करोड़ रु. की वृद्धि पाते हैं। चूंकि समान अवधि के दौरान कर्मचारियों और ऋणदाताओं सहित अन्य शेयरधारकों के मूल्यों में बदलाव की कोई सूचना नहीं मिली, इसलिए 33,000 करोड़ रु. की वृद्धि, बीपीसीएल के समग्र कंपनी मूल्य में स्पष्ट वृद्धि और जिसके चलते राष्ट्रीय संपत्ति में समान राशि की वृद्धि दर्शाती है।

9.2 चूंकि शेयर बाजार किसी कंपनी के वायदा नकदी प्रवाह के मौजूदा मूल्य को प्रदर्शित करता है, मूल्य में वृद्धि बीपीसीएल की दक्षता में सुधार से प्रत्याशित लाभ

चित्र 1: बीपीसीएल और एचपीसीएल के शेयर मूल्यों की तुलना



स्रोत: बीएसई

प्रकट करती है जब उसकी तुलना एचपीसीएल से की गई, जो सरकार के नियंत्रणाधीन रहेगी। सामरिक विनिवेश का मार्गदर्शन आधारभूत आर्थिक सिद्धांत द्वारा किया जाता है कि सरकार को विनिर्माण/माल उत्पादन और सेवा क्षेत्रों में अपनी संलिप्तता समाप्त कर देनी चाहिए जहां प्रतिस्पर्धी बाजारों ने विकास की

पराकाष्ठा प्राप्त कर ली है। विभिन्न कारकों के कारण ऐसी कंपनियों के निजी हाथों में बेहतर निष्पादन करने की संभावना है जैसे प्रौद्योगिकी उन्नयन और कार्यक्षम प्रबंधन पद्धतियां; और इस प्रकार संपत्ति का सृजन करेंगे तथा देश की आर्थिक प्रगति में योगदान करेंगे। इसलिए एचपीसीएल के साथ तुलना करने

<sup>1</sup> <https://www.livemint.com/market/mark-to-market/why-privatization-of-bpcl-will-be-a-good-thing-for-all-stakeholders-1568309050726.html>

पर बीपीसीएल के मूल्य वृद्धि इन प्रत्याशित लाभों को प्रकट करती है। अनेक देशों में फैली वित्तीय अर्थव्यवस्थाओं में विस्तृत साहित्य स्पष्ट रूप से यह प्रमाणित करता है कि निजीकरण ऊपर उल्लिखित

स्रोतों से महत्वपूर्ण दक्षता लाभ लाता है (बॉक्स 2 देखें)। इस परिप्रेक्ष्य में सुश्री मार्गरेट थैचर के नेतृत्व में यू के का अनुभव विशेषरूप से विचारणीय है। (बॉक्स 1 देखें)।

### बाक्स 1 यूके का निजीकरण मॉडल

ब्रिटिश निजीकरण कार्यक्रम 1980 में यूनाइटेड किंगडम (यूके) की तत्कालीन प्रधानमंत्री मार्गरेट थैचर के प्रबंधन में शुरू किया गया था। आरंभिक चरण (1979-80) में, राजस्व में वृद्धि करने और इस प्रकार ब्रिटिश एयरोस्पेस एंड केबल एंड वायरलेस जैसी कंपनियों में सार्वजनिक क्षेत्र की उधारी कम करने के लिए पहले से लाभप्रद कंपनियों के निजीकरण पर फोकस था। अगले चरण (1982-86) में, मूल उपादेयताओं के निजीकरण की ओर फोकस स्थानांतरिक हो गया और सरकार ने जगुआर, ब्रिटिश टेलीकॉम, केबल एंड वायरलेस ब्रिटिश एयरोस्पेस, ब्रिट ऑयल तथा ब्रिटिश गैस के शेष हिस्से को बेच दिया। सबसे आक्रामक चरण (1987-91) में, ब्रिटिश स्टील, ब्रिटिश पेट्रोलियम, रोल्स-रॉयश, ब्रिटिश एयरवेज, वाटर एंड इलैक्ट्रोसिटी को बेच दिया गया।

कंपनी के सभी या कुछ शेयरों की प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के माध्यम से मुख्य पद्धति थी। ब्रिटिश एयरोस्पेस का निजीकरण 1981 में इसके 52 प्रतिशत शेयरों के आईपीओ द्वारा किया गया था जिसके शेष शेयरों को बाद के वर्षों में बेचा गया था। 1984 में दि ब्रिटिश टेलीकॉम (आईपीओ) का आईपीओ बड़े पैमाने पर शेयर की पेशकश थी और उस तारीख तक विश्व इतिहास में सबसे बड़ी शेयर पेशकश में दो मिलियन से अधिक नागरिकों ने भाग लिया। दि ओईसीडी (2003:24) ने बीटी निजीकरण को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर “बड़े पैमाने पर निजीकरण की शुरूआत का अग्रदूत” कहा था। बाद के वर्षों में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश गैस, ब्रिटिश स्टील, इलॉक्ट्रिक उपादेयताओं, और अन्य कंपनियों में बड़े पैमाने पर शेयर की पेशकश की। दूसरी निजीकरण की पद्धति प्रत्यक्ष बिक्री या व्यापार बिक्री, जिसमें बातचीत या प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से मौजूदा निजी कंपनी को कोई अन्य कंपनी बेचना शामिल है। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश एरोस्पेस को रोबर ऑटो मोबाइल और रॉयल आर्डनेंस की बिक्री की थी। निजीकरण की दिशा में जो अन्य सीधी बिक्री हुई है उनमें ब्रिटिश शिपबिल्डर्स, सीलिंग फेरीज और दी टोटे आते हैं। ब्रिटेन के नेशनल फ्रंट कॉर्पोरेशन को 1982 में कम्पनी के कर्मचारियों को बेच दिया गया था और लंदन की बस सेवाओं को 1994 में कम्पनी के प्रबंधकों और कर्मचारियों को बेच दिया गया था।

अधिकतर मामलों में ब्रिटेन में निजीकरण के विनियामक संरचनाओं में सुधार लाये जाने के साथ-साथ ही किया गया था। सरकार इस बात को समझती है कि जहां भी सम्भव हो निजीकरण को खुली प्रतियोगिता के साथ किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर ब्रिटिश टेलीकॉम पोस्ट ऑफिस से अलग हो गया था और इसके पहले कि इसके शेयर्स जनता में बेचे जाते, सरकार से दूरी बनाते हुए इसकी स्थापना एक निगम के रूप में कर दी गयी थी। फिर उसके बाद कुछ समय बीत जाने पर सरकार के इसके प्रतिस्पर्धास्वरूप बीटी की स्थापना की थी। प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने के लिए ही ब्रिटिश सरकार ने 1980 में इंटरसिटी बस सेवा शुरू की थी। इस अभियान के बाद राज्य के स्वामित्व वाली बस लाइन जैसे कि नेशनल एक्सप्रेस का भी निजीकरण कर दिया गया था। 1980 के दशक में ढेर सारे ब्रिटिश सीपोर्ट्स का निजीकरण हुआ था और सरकार ने उन श्रमिक संघ कानूनों में सुधार किया था जिनके कारण उद्योगों का कामकाज ठप पड़ गया था। फ्लोरिया (2004) ने यूके में किये गये निजीकरण में किये अपने व्यापक अनुसंधान में यह पाया है कि इस प्रकार पर्दाफाश से शेयर होल्डरों और कर्मचारियों (विशेषकर प्रबंधकों) को लाभ मिला है तथा फर्मों और अन्य कर्मचारियों पर थोड़ा प्रभाव पड़ा है। किये गये क्षेत्र विशिष्ट अध्ययन (एफ्फ्यूसो, एंगेरिज, और पोल्लिट्ट, 2009) में यह पाया गया है कि यूके में रेल कम्पनियों का जो निजीकरण हुआ था उससे कार क्षमता में काफी वृद्धि हुई थी। पार्कर (2004) ने पाया है कि निजीकरण से प्रतिस्पर्धापरक बाजार पैदा हो सकेंगे।

### बाक्स 2 निजीकरण के लाभ के प्रमाण

ब्राउन एट एल (2015) ने पाया है कि निजीकरण का औसत प्रभाव खासतौर से सकारात्मक रहा है जो कि अनुमानतः लगभग 5-12% होता है लेकिन इनमें देश-दर-देश और समयावधि के साथ-साथ अंतर भी देखा गया है। इसका सकारात्मक प्रभाव फर्मों की बेहतर गुणवत्ता और समष्टिगत अर्थव्यवस्था और संस्थापरक परिवेश के रूप में भी देखा

गया है। छिब्वर और गुप्ता (2017) ने बताया है कि विनिवेश का श्रमिक उत्पादकता पर काफी सकारात्मक प्रभाव पड़ा है और भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की सम्पूर्ण क्षमता भी बढ़ी है। ओ टूले एवं अन्य (2016) ने वियतनाम में किये अपने अध्ययन में यह पाया है कि निजीकरण किये जाने और साझेदारी से पूंजी के आवंटन में सुधार आया है और आर्थिक क्षमता भी बढ़ी है। चेन एवं अन्य (2008) ने बताया है कि चीनी कम्पनियों के कामकाज में, विशेषकर जब इनके नियंत्रण स्वामित्व का अंतरण हुआ था में खास सुधार देखा गया है जो कि मुख्य रूप से लागत में कमी किये जाने के कारण आयी थी लेकिन ऐसा तभी हुआ जब इनका नया मालिक कोई गैर सरकारी व्यक्ति था। सब्रमणियन, के. और मेगिनसन, डब्ल्यू (2018) ने पाया है कि सख्त रोजगार संरक्षण कानूनों (EPL) से निजीकरण नहीं हो पाता है और इसईपीएल का निजीकरण पर प्रभाव उद्योग के क्षेत्र में बहुत व्युत्क्रमानुपाती होता है जहां दरें जितनी ज्यादा होती हैं उत्पादन उतना ही कम होता है। मेगिनसन और नेट्टर (2001), बोर्डमेन और विनिंग (1989), ला पोर्टा और लोपेज डे सिलेंस (1999) ने पाया है कि निजीकरण के बाद के दौर में फर्मों को अधिक लाभ मिला है उनकी क्षमता भी बढ़ी है, सामान्य रूप से निवेश का स्तर बढ़ा है, परिणाम भी ज्यादा आये हैं, लाभांश भी ज्यादा मिले हैं और निजीकरण के बाद इसका लाभ भी कम लिया गया है। गुप्ता (2005) के अनुसार लाभ प्रदाता, श्रमिक उत्पादकता और निवेश खर्च के स्तर और वृद्धि दर दोनों में विशेष सुधार आया है जो कि आंशिक निजीकरण के कारण हुआ है। मजूमदार (1996) ने कहा है कि राज्य के स्वामित्व वाले उपक्रमों की अपेक्षा यहां की कार्य क्षमता का स्तर काफी ऊंचा है जिससे यह प्रकट होता है कि इस क्षमता अभियान के दौरान केवल कमी आयी है ऐसा 1973-89 की अवधि के भारतीय फर्मों के अध्ययन से पता चलता है।

बोरीसोवा और मेगिनसन (2010) ने संकेत दिया है कि औसतन सभी फर्मों में सरकारी स्वामित्व में एक प्रतिशत की जो कमी आयी है उसका संबंध उस क्रेडिट के प्रसार से है जिसका प्रयोग ऋण पर आने वाले खर्च के रूप में अप्रत्यक्ष रूप से हुआ है। यह संगणना तीन तिमाही को आधार मानकर की गयी है। स्प मज सं (2016) के अनुसार ऋणात्मक सूचीकरण प्रभाव के समायोजन के बाद नयी निजीकरण कम्पनियों के लाभ में खास वृद्धि (23 प्रतिशत पॉवरइन्टस) देखी गयी है। ट्रिपल डिफ्रेंस-इन-डिफ्रेंस परीक्षण के आधार पर भी पूंजीगत का संबंध कामकाज में महत्वपूर्ण और व्यापक सुधार से रहा है जो 7 वर्ष की अवधि (-3 से + वर्षों तक) में देखा गया है Oum at al (2006) के अनुसार इस बात के पुख्ता प्रमाण हैं कि वे एयरपोर्ट्स जो कि ज्यादातर सरकारी स्वामित्व में हैं और बहुस्तरीय सरकारी स्वामित्व में हैं, कार्य क्षमता की दृष्टि से उन एयरपोर्ट्स से कम स्तर के हैं जो निजी स्वामित्व में काम कर रहे हैं। ग्राहकों की बढ़ती हुई संतुष्टि, टेरिफ में होने वाली कटौती, दूर संचार के क्षेत्र में डाटा के बढ़ते उपयोग, ग्रामीण क्षेत्रों में फैलती बैंकिंग सेवाओं और रेलवे के ग्राहकों की अपेक्षा हवाई जहाज के भाड़े में की जाने वाली कटौती के रूप में होता है।

9.3 निजीकरण की लाभ क्षमता की जांच परख करने और यह देखने की भारतीय संदर्भ में निजीकरण के लाभ दिखाई भी दे रहे हैं, क्या नहीं, इस बात का विश्लेषण इस अध्याय में किया गया है। उन 11 सीपीएसई के कामकाज के देखते हुए किया गया

है जिनमें 1999-2000 से 2003-04 में विनिवेश किया गया था। वर्तमान विनिवेश अभियान के लिए ऐतिहासिक संदर्भ जुटाने के लिए नीचे बॉक्स 3 में भारत के विनिवेश नीति के प्रगति का मूल्यांकन किया गया है।

### बाक्स 3 भारत की विनिवेश नीति का क्रमिक विकास

1991 में शुरू किये गये उदारीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के निजीकरण/निवेश की मांग बढ़ गयी है। प्रारम्भिक चरण में नीलामी के माध्यम से, सामूहिक रूप से छोटे-छोटे स्टेक की बिक्री करके किया गया था। इसके बाद आने वाले वर्षों में प्रत्येक कम्पनी की अलग-अलग बिक्री की गयी थी। यह प्रक्रिया 1999-2000 तक चली। भारत ने 1999-2000 में एक नीतिगत उपाय के तौर पर बिक्री की प्रक्रिया शुरू की जिसके अंतर्गत कुछ अभिज्ञात केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों में सरकार के 50% या इससे अधिक की हिस्सेदारी का काफी हिस्से बेचा गया और साथ ही प्रबंधनपरक नियंत्रण का अंतरण किया गया। यह प्रक्रिया मॉडर्न फूड इन्डस्ट्रीज लि. (एमएफआईएल) में सरकार की हिस्सेदारी के 74% की बिक्री से शुरू की हुई थी। इसके पश्चात 12 सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों (जिनमें इन सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठानों के सहायक उपक्रम भी शामिल थे) और 17 होटल्स जो कि इण्डियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (आईटीडीसी) की निजी क्षेत्र को बिक्री कर दी गयी थी और साथ ही में सरकार ने प्रबंधनपरक

नियंत्रण का भी अंतरण कर दिया था। इसके अलावा इंडो ब्राइट पेट्रोलियम (आईबीपी) में 33.58% की भागीदारी इण्डिया ऑयल कॉर्पोरेशन को कर दी गयी थी। हालांकि इस रणनीतिक बिक्री के बावजूद भी आईबीपी एक सार्वजनिक क्षेत्रीय प्रतिष्ठान बना रहा क्योंकि आईओसी ने अपनी पेट-इक्विटी 53.58 बनाए रखी। विनिवेश की नीति में दूसरा प्रमुख बदलाव 2004-05 में आया। जब यह निर्णय लिया गया था कि सरकार अपनी इक्विटी को तरल कर सकती है और अपने संशोधनों को बढ़ा सकती है जिससे कि जनता की सामाजिक जरूरतें पूरी की जा सकें। यह बात पहले की रणनीति बिक्री से स्पष्ट रूप से हटकर हुई है।

रणनीतिक बिक्री के कार्य में 2014 के बाद से नया मोड़ आया था। 2016-17 से 2018-19 के दौरान औसतन विनिवेश से प्राप्त होने वाली कुल राशि के लगभग 28.2% की बिक्री हुई थी। इस दिशा में विनिवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआईपीएएम) ने मई, 2016 में एक व्यापक दिशा निर्देश तैयार किये हैं। जिन्हें "सीपीएसई की पूंजी पुर्नसंख्या" के नाम से जाना जाता है। इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के समाधान किये गये थे जैसे कि लाभांश का भुगतान, शेयरों की वापस खरीद, बोनस शेयर को जारी करना और शेयरों को अलग-अलग भागों में तोड़ना। सरकार ने निम्नलिखित तरीकों से सीपीएसई में विनिवेश सक्रिय नीति अपना रही है:

- i. अनुसूचित सीपीएसई में छोटी-माटी भागीदारी का विनिवेश जिससे कि 25% के न्यूनतम सार्वजनिक भागीदारी के मानक को प्राप्त किया जा सके।

सीपीएसई का विनिवेश करते समय सरकार मुख्य हिस्सेदारी अर्थात् 51% और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम का प्रबंधन नियंत्रण अपने पास रखेगी।

- ii. लोगों को स्वामित्व की सुविधा देने हेतु और उसके स्टैकधारकों को जवाबदेगी के माध्यम से कंपनियों की क्षमता को बढ़ाने के लिए सीपीएसई को लिस्टिंग की गई है-57 पीएसयू को अब तक सूचीबद्ध किया जा चुका है जिनका कुल बाजार पूंजीकरण 13 लाख करोड़ से अधिक है।

- iii. स्ट्रैटिजिक विनिवेश;

- iv. बड़े पीएसयू द्वारा जिनके बहुत अधिशेष हैं, शेयरों का बायबैक;

- v. एक ही क्षेत्र में पीएसयू के बीच विलयन और अधिग्रहण;

- vi. एकसचेंज ट्रेडेडफंड (ईटीएफ) का आरंभ-एक इक्विटी इंस्ट्रुमेंट है जो एक विशेष इंडेक्स को ट्रैक करता है। सीपीएसई ईटीएफ भारत की मुख्य सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों जैसे ओएनजीसी, आरईसी, कोल इंडिया, कंटेनर कॉर्प, ऑयल इंडिया, पावर फाइनेंस, गेल, बीईएल, ईआईएल, इंडियन ऑयल और बीईएल, ईआईएल, इंडियन ऑयल और एनटीपीसी में इक्विटी निवेशों से बना है; और

- vii. सीपीएसई की चयनित परिसंपत्तियों का मुद्राकरण किया जाए ताकि उनकी बैलेंस शीट को बेहतर किया जा सके। उन के ऋण को कम किया जा सके और उनके पूंजीगत व्यय की आवश्यकताओं के एक हिस्से का पूरा किया जा सके।

नीति आयोग ने स्ट्रैटिजिक विनिवेश हेतु पीएसयू की पहचान को अनिवार्य कर दिया है। इस उद्देश्य हेतु, नीति आयोग ने पीएसयू को "उच्च प्राथमिकता" और "निम्न प्राथमिकता" में वर्गीकृत किया है जोकि (क) राष्ट्रीय सुरक्षा (ख) कम से कम सरकारी हस्तक्षेप और (ग) बाजार अपूर्णता और लोक प्रयोजन के आधार पर किया गया है। त्वरित निर्णय लेने को सुकर बनाने, सीपीएसई के स्ट्रैटिजिक विनिवेश के सभी मामलों में निम्नलिखित पर निर्णय लेने की शक्तियां एक वैकल्पिक तंत्र को प्रत्यायोजित की गई हैं जहां आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल संबंधी (सीसीईए) ने स्ट्रैटिजिक विनिवेश के लिए सिद्धांततः अनुमोदन दिया गया है।

- (i) लेन-देन किए जाने वाले शेयरों की मात्रा, बिक्री का माध्यम और लेन-देन का अंतिम न्यूनन अथवा ऐसे मूल्य हेतु नियमों दिशानिर्देशों को रखना; और स्ट्रैटिजिक पार्टनर/खरीदार का चयन; बिक्रर के नियम एवं शर्तें; और

(ii) विनिवेश के कोर समूह (सीजीडी) के प्रस्तावों पर समय, मूल्य बिक्री के नियम एवं शर्तों और लेन-देन से संबंधित अन्य मुद्दों के संबंध में निर्णय लेना।

20 नवंबर, 2019 को सरकार ने घोषणा की कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लि. (बीपीसीएल), भारतीय नौवहन निगम लिमिटेड (एससोआई) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) और भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड (कॉनकॉर) के खरीदारों को पूर्ण प्रबंधन नियंत्रण सौंप दिया जाएगा। 8 जनवरी 2020 को मिनरल्स एंड मेटल्स ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमएमडीसी), राष्ट्रीय खनिज विकास निगम (एनएमडीसी), एमईसीओएन और भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (बीएचईएल) के लिए स्ट्रैटिजिक विनिवेश को मंजूरी दी गई।

## निजीकरण का प्रभाव: फर्म स्तर का विश्लेषण

9.4 निजीकरण के पहले और बाद में चयनित सीपीआई पर स्ट्रैटिजिक विनिवेश/निजीकरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए हमने 11 पीएसई का अध्ययन किया जिनका 199-2000 से 2003-2004 तक स्ट्रैटिजिक विनिवेश हुआ था जिनके संबंध में

निजीकरण के पहले और बाद में डाटा उपलब्ध है। डिफरेंस-इन-डिफरेंसिस पद्धति का प्रयोग करते हुए, सावधानी से तुलना करने हेतु, इन सीपीआई की उसी इंडस्ट्री समूह (तालिका 1) में उनकी समकक्ष कंपनियों के साथ तुलना की गई है। बॉक्स 4 में डिफरेंस-इन-डिफरेंसिस पद्धति का स्पष्टीकरण दिया गया है।

सारणी 1: चयनित सीपीएसई और समकक्ष कंपनियों की सूची

उद्योग समूह	निजीकृत सीपीएसई	समकक्ष कंपनी
धातु-अलॉय	हिन्दुस्तान जिंक	टिनप्लेट का. ऑफ इंडिया, हिन्दुस्तान कॉपर, वेदांता
अल्युमीनियम एवं अल्युमीनियम उत्पाद	भारत अल्युमीनियम कंपनी लि. (बीएलसीओ)	नालको, हिंडालको, पीजी फॉइलस
कम्प्यूटर, पेरिफेरल्स एवं एटोरेज डिवाइस	कंप्यूटर मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन लि. (सीएमसी)	मोसरबेयर, जेनिथ कम्प्यूटर्स, इजमो लिमिटेड
ऑटोमोबाइल	मारुति सुजुकी	अशोक लेलैंड लि., टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा लि.
पेट्रोकेमिकल्स	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लि. (आईपीसीएल)	केमप्लास्ट सन्मार, भंसाली इंजिनियरिंग पॉलीमर्स, इनियोस स्टायशैन्यूशन इंडिया लि.
दूर संचार सेवाएं	दूर संचार सेवाएं	टाटा टेलिसर्विसेस, एनटीएनएल, जीटीएस इफ्रा
हेवी इंजिनियरिंग	लगान इंजिनियरिंग	गुजरात टूलरूम, गुजरात टेक्सट्राॅनिक्स, इंडिया इंजिनियरिंग इंडिया लि.

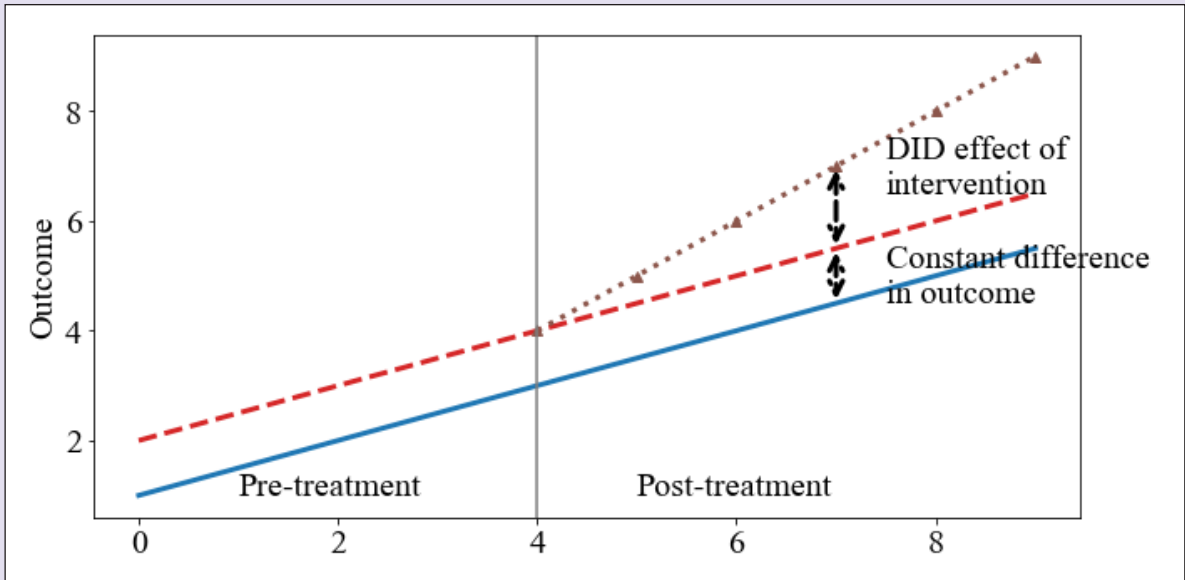
<sup>2</sup> वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक कर अवधि में निजीकरण की जाने वाली 30 सी.पी.एस.ई. में से 18 एंटरप्राइज भारतीय पर्यटन विकास निगम लि. की सब्सिडी एंटरप्राइज थीं और एक एंटरप्राइज होटल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (एच.सी.आई) की सब्सिडी थी। हमारे विश्लेषण के प्रयोजन के लिए, हमें प्रत्येक विनिवेशित कंपनी की निजीकरण पूर्व और पश्चात् 10 वर्ष की अवधि के सभी वित्तीय कार्यानिष्पादन सूचकों की सूचना की आवश्यकता थी। तथापि आई.टी.डी.सी. की 18 तथा एच.सी.आई. की एक एंटरप्राइज के विनिवेशित सब्सिडियों के मामले में वित्तीय विवरण को 'मूल कंपनी' के समेकित वित्तीय विवरण में सम्मिलित कर दिया गया था। विनिवेश के पश्चात् इन सब्सिडियों को क्रेता कंपनियों के साथ जोड़ दिया गया था और वित्तीय विवरण को फिर से 'नई मूल कंपनी' के समेकित विवरण प्रस्तुत किया गया था। इस समस्या के कारण इन सब्सिडी एंटरप्राइज को हमारे विश्लेषण में सम्मिलित नहीं किया जा सका। इंडोब्रिटिश पेट्रोलियम (आई.बी.पी.) प्राइवेट लि. का विलय इंडियन ऑयल कार्पोरेशन (आईओ.सी.) के साथ किया गया था जोकि एक सरकारी उद्यम है और इसलिए विश्लेषण में इस पर विचार नहीं किया गया।

मीडियम एवं लाइट इंजिनियरिंग	जेसोप एंड कॉ.	इलिंग अल्ट्रा, दिसा इंडिया, अल्फा लवल, किल्ट्रॉन इंजिनियर्स
बेकरी उत्पाद	माडर्न फूड इंडिया लि.	ब्रिटानिया
वायर्स एच केबल्स	हिन्दुस्तान टेलिप्रिंटर्स (एचटीएल)	अनामिका कंडक्टर्स, डेल्टन केबल्स, फॉर्ट गल्लेस्टर लि.
केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स	पारादीप फोस्फेट्स	जीएसएफसी, फर्टिलाइजर्स एंड कमिकल्स-त्रावणकोर, गोदावरी के मिक्ल्स एंड फार्टिलाइजर्स
<b>कुल</b>	<b>11</b>	<b>32</b>

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

#### बाक्स 4 डिफरेंस-इन-डिफरेंस पद्धति

डिफरेंस-इन-डिफरेंस (डीआईडी) एक सांख्यिकीय तकनीक है जिसका प्रयोग विशिष्ट हस्तक्षेप अथवा व्यवहार (जैसे कि कानून का परित्र होना, नीति का अधिनियमन, अथवा बडे पैमाने पर कार्यक्रम का क्रियान्वयन) कर आकलन करने के लिए किया जाता है। यह तकनीक एक जनसंख्या जोकि विशिष्ट हस्तक्षेप (एक व्यवहार समूह) द्वारा प्रभावित हैं एवं एक जनसंख्या जोकि (एक नियंत्रण समूह) नहीं है, के मध्य समयावधि के दौरान परिणामों में परिवर्तनों की तुलना करती है। डीआईडी का उपयोग आमतौर पर किसी हस्ताक्षेप के अनुमानित प्रभाव को प्रभावित करने वाले किसी भी बाहरी कारकों की संभावना को कम करने के लिए किया जाता है।

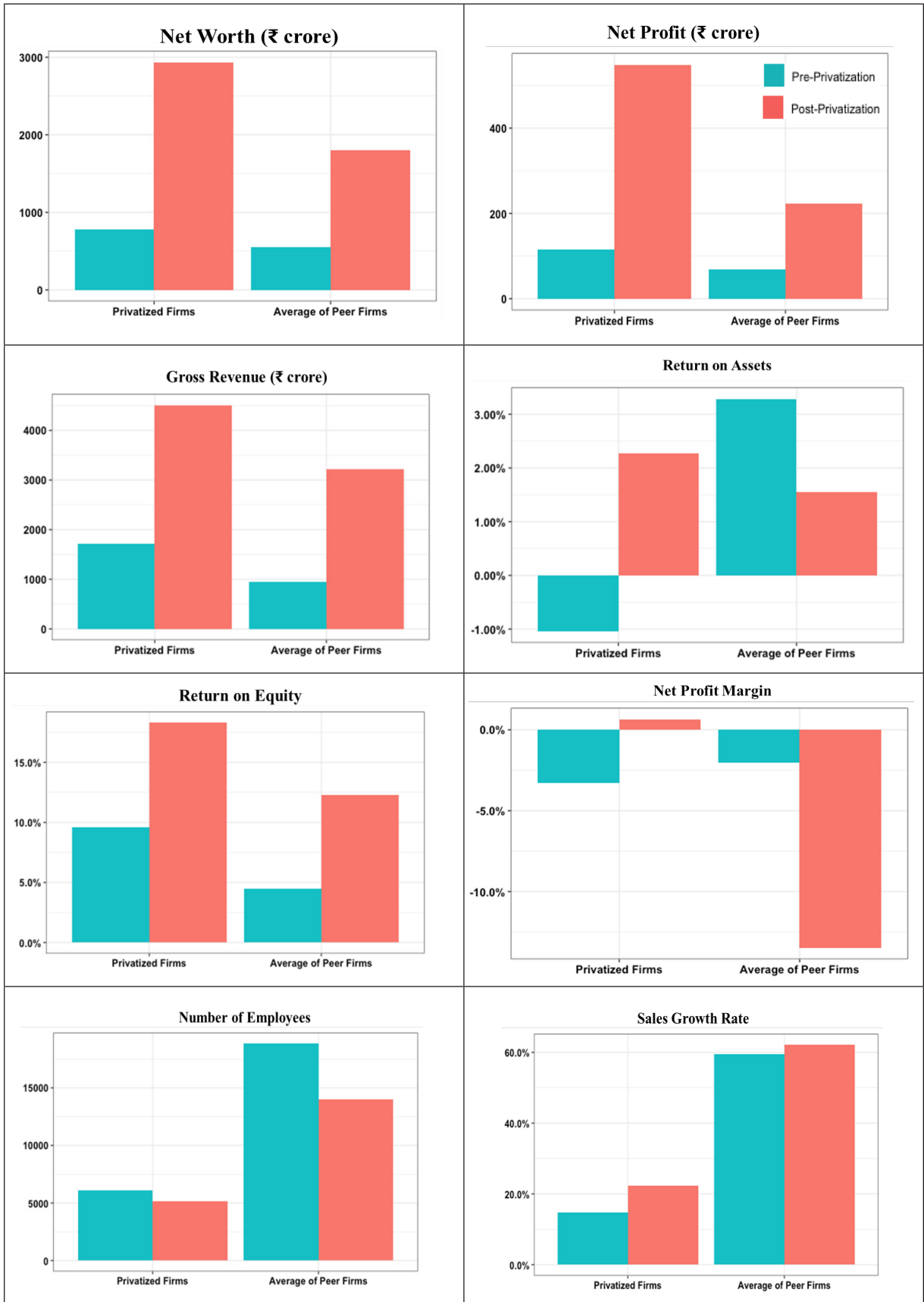


9.5 आकृति 2 विशिष्ट सीपीएसई के निजीकरण के वर्ष के पहले और बाद के दस वर्षों के लिए विभिन्न वित्तीय संकेतकों का प्रयोग करते हुए उनकी समकक्ष कंपनियों से तुलना करते हुए उनकी समकक्ष कंपनियों से तुलना करते हुए उनकी समकक्ष कंपनियों से तुलना करते हुए इन सीपीएसई का औसत कार्य-निष्पादन दर्शाती है। आकृति 2 से यह स्पष्ट है कि निजीकृत फर्मों के कार्य-निष्पादन में निजीकरण के

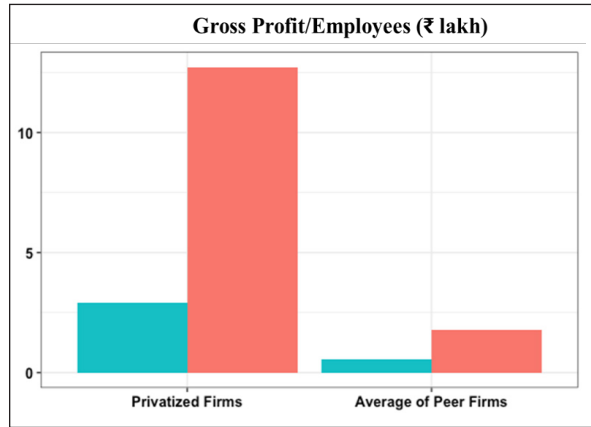
बाद उसी अवधि के दौरान समकक्ष फर्मों के कार्य निष्पादन में अंतर का प्रयोग करते हुए भ्रमित करने वाले अन्य कारकों को नियंत्रित करने के बाद काफी सुधार आया है। चित्र 2 से यह स्पष्ट होता है कि निजी फर्मों के निष्पादन में उसी समय में सहयोगी फर्मों के निष्पादन के अंतर में अन्य उलझाने वाले कारकों को नियंत्रण करने के बाद निजीकरण को अपनाते हुए उल्लेखनीय सुधार हुआ।

<sup>3</sup> डाटा सीमाओं को मानते हुए एमएफआईएल और आईपीसीएल को उनके विनिवेश के पश्चात 10 वर्षों से कम समय तक लिया गया है।

चित्र 2: निजी फर्मों के साथ-साथ सहयोगियों के वित्तीय संकेतकों का तुलनात्मक







स्रोत: सीएमआईसी कौशल पर आधारित सर्वे गणना

9.6 अब हम प्रत्येक मीट्रिक की भिन्नताओं का विस्तार में व्याख्या करेंगे।

i) कुल मूल्य: कंपनी का कुल मूल्य उसकी इक्विटी शेयरहोल्डर है। इसमें शेचयरहोल्डरों द्वारा किया गया पूंजी भंडारणों के रूप में, सृजित लाभ के कंपनी के औसतन

निजी फर्मों में निजीकरण से पूर्व 700 करोड़ से बढ़कर निजीकरण के बाद 2992 करोड़ वृद्धि हुई, वित्तीय स्वास्थ्य बढ़कर महत्वपूर्ण सुधार हुआ और शेयरहोल्डरों के लिए धन संपत्ति सृजन में वृद्धि हुई (तालिका 2) \*निजीकरण के कारण अंतर में अंतर विश्लेषण का आकलन में 803.3 करोड़ रु. की वृद्धि हुई।

तालिका 2: कुल मूल्य ( करोड़ रु. में )

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	656.25	1921.60	1265.35
2 सीएमसी	35.28	275.41	240.13
3 मारुति	1426.02	8191.98	6765.96
4 जेसोप	-212.07	77.19	289.26
5 लगान इंजीनियरिंग	5.15	6.30	1.15
6 आईपीसीएल	2258.52	3106.69	848.17
7 एचटीएल	33.35	-145.98	-179.33
8 हिंदुस्तान जिंक	818.06	12874.57	12056.51
9 मॉडल फूड इंडिया	10.63	-79.34	-89.97
10 पारादीप फासफेट	-3.98	214.12	218.1
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	2683.82	6468.49	3784.67
12 सभी निजी फर्मों का संयुक्त औसत	701.00	2991.91	2290.91
13 सहयोगी फर्मों का संयुक्त औसत	551.61	1802.14	1250.53
14 निजी फर्म घटा कर सहयोगी फर्म	149.39	1189.77	<b>DiD = 1040.38</b>

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

ii) कुल लाभ: यह कंपनी का कर के बाद का कुल लाभ है। सभी प्रचालन खर्चों को मिलाने के बाद कंपनी को कुल लाभ में वृद्धि कंपनी की बहुत अधिक वसूली को दर्शाता है। सहयोगी कंपनियों की तुलना में औसतन

निजी फर्मों का कुल लाभ निजीकरण से पहले 100 करोड़ रु. से बढ़कर निजीकरण के बाद 555 हो गया (तालिका 3 निम्नलिखित। निजीकरण के कारण अंतर में अंतर विश्लेषण आकलन में 244.3 करोड़ की वृद्धि हुई।

तालिका 3: कुल लाभ ( करोड़ रु. में )

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	45.47	348.94	303.47
2 सीएमसी	6.77	73.22	66.45
3 मारुति	205.28	1321.99	1116.71
4 जेसोप	-36.44	7.87	44.31
5 लगान इंजीनियरिंग	-0.49	0.18	0.67
6 आईपीसीएल	238.48	606.42	367.94
7 एचटीएल	3.16	-43.84	-47
8 हिंदुस्तान जिंक	72.47	3237.04	3164.57
9 मॉडल फूड इंडिया	-1.2	-18.4	-17.2
10 पारादीप फास्फेट	-53.93	114.83	168.76
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	620.34	452.25	-168.09
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	100	554.6	454.6
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	68.51	222.84	154.33
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	31.49	331.76	DiD=300.27

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

iii) सकल राजस्व: औसतन, निजीकृत फर्मों का सकल राजस्व, जो निजीकरण से पहले 1560 करोड़ रूपये था निजीकरण के बाद बढ़कर 4653 करोड़ रूपये हो गया। निजीकरण के बाद, माल की बिक्री और अन्य गैर-वित्तीय गतिविधियों से आय में वृद्धि का संकेत मिला (तालिका 4)। डीआईडी विश्लेषण, निजीकरण को सकल राजस्व में 827.65 करोड़ रूपये की वृद्धि का श्रेय देता है।

iv) आस्तियों पर लाभ (आरओए): आरओए, प्रतिशत के रूप में व्यक्त की गई कंपनी की कुल औसत संपत्ति

पर करों के अधिरोपण (पीएटी) के बाद मुनाफे की दर को अभिग्रहण करता है। निजीकृत फर्मों के लिए औसतन, आरओए (-) 1.04 प्रतिशत से बढ़कर 2.27 प्रतिशत हो गया है, जो कि पीयर फर्मों से भी अधिक है, जो यह इंगित करता है कि निजीकृत फर्म अपने संसाधनों का अधिक उत्पादक ढंग से उपयोग करने में सक्षम हैं (तालिका 5)। डीआईडी विश्लेषण, आरओए में 5.04 प्रतिशत की वृद्धि का श्रेय निजीकरण को देता है।

तालिका 4: कुल राजस्व ( करोड़ रु. में )

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	747.84	2858.48	2110.64
2 सीएमसी	261.55	792.88	531.33
3 मारुति	6013.28	22958.8	16945.52
4 जेसोप	79.76	178.33	98.57
5 लगान इंजीनियरिंग	6.52	12.87	6.35
6 आईपीसीएल	3791.56	9341.25	5549.69
7 एचटीएल	141.21	126.89	-14.32
8 हिंदुस्तान जिंक	999.16	7923.77	6924.61
9 मॉडल फूड इंडिया	77.21	192.6	115.39
10 पारादीप फास्फेट	824.52	2692.56	1868.04
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	4219.51	4106.69	-112.82
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	1560.19	4653.19	3093
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	945.42	3210.77	2265.35
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	614.77	1442.42	<b>DiD=827.65</b>

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

तालिका 5: परिसंपत्तियों की वसूली ( प्रतिशत )

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	4.62	6.84	2.22
2 सीएमसी	-0.89	8.7	9.59
3 मारुति	8.24	10.29	2.05
4 जेसोप	-35.95	4.34	40.29
5 लगान इंजीनियरिंग	-2.19	0.78	2.97
6 आईपीसीएल	4.34	6.74	2.4
7 एचटीएल	-3.12	-24.17	-21.05
8 हिंदुस्तान जिंक	5.29	26.7	21.41
9 मॉडल फूड इंडिया	3.35	-39.5	-42.85
10 पारादीप फास्फेट	-8.78	2.57	11.35

11 टाटा कम्यूनिकेशंस	13.4	4.03	-9.37
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	-1.04	2.27	3.31
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	3.28	1.55	-1.73
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	-4.32	0.72	<b>DiD=5.04</b>

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

v) इक्विटी पर रिटर्न (आरओई): इक्विटी पर रिटर्न औसत निवल मूल्य के रूप में कर पश्चात् प्राप्त लाभ (पीएटी) है। औसतन, निजीकृत फर्मों का इक्विटी पर रिटर्न (आरओई) निजीकरण से पूर्व 9.6 प्रतिशत था जो निजीकरण के पश्चात् बढ़कर 18.3 प्रतिशत हो गया,

जिससे शेयरधारकों की इक्विटी की प्रत्येक इकाई से लाभ कमाने की फर्म की क्षमता को पता चलता है। औसत सहकर्मी समूह के संबंध में निजीकरणपूर्व की प्रत्येक अवधि के लिए आरओई में वृद्धि 7.8 प्रतिशत थी (तालिका 61)। डीआईडी विश्लेषण में आरओई में 0.89 की वृद्धि का श्रेय निजीकरण को दिया गया है।

तालिका 6: इक्विटी पर रिटर्न ( प्रतिशत )

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	6.1	16.9	10.8
2 सीएमसी	11.2	26.6	15.4
3 मारुति	19	16.6	-2.4
4 जेसोप	5	12.9	7.9
5 लगान इंजीनियरिंग	-4.5	1.4	5.9
6 आईपीसीएल	11.2	17.9	6.7
7 एचटीएल	9.8	2.3	-7.5
8 हिंदुस्तान जिंक	9.2	28.8	19.6
9 मॉडल फूड इंडिया	11.4	27.8	16.4
10 पारादीप फास्फेट	3.5	-0.1	-3.6
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	-44.8	7.3	52.1
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	9.6	18.3	8.7
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	4.5	12.31	7.81
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	5.1	5.99	<b>DiD=0.89</b>

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

vi) *निवल लाभ मार्जिन (गुंजाइश)*: किसी कंपनी का निवल लाभ मार्जिन उसकी कुल आय का करोत्तर प्रतिशत होता है। औसतन, निजीकृत फर्मों के निवल लाभ मार्जिन में वृद्धि हुई है, निजीकरण से पूर्व यह मार्जिन (गुंजाइश)-3.24: था और निजीकरण के पश्चात् यह 0.65: हो गया है जो प्रतिबिम्बित करता है कि आय के रूप में सृजित होने वाले रुपये के करोत्तर

लाभ के अंश में वृद्धि हुई है। समकक्ष कंपनियों के समूहों के निवल लाभ मार्जिन, निजीकरण पूर्व अवधि की तुलना में निजीकरणोत्तर अवधि में -2.03 प्रतिशत से घटकर -13.47 हो गए हैं। (तालिका 7)। डिफ्रेंस इन डिफ्रेंस विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण के कारण निवल लाभ मार्जिन में 15.26: की वृद्धि हुई है।

तालिका 7: निवल लाभ मार्जिन (प्रतिशत)

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	5.8	10.1	4.3
2 सीएमसी	1.9	9.1	7.2
3 मारुति	6.5	34.3	27.8
4 जेसोप	2.9	-66.9	-69.8
5 लगान इंजीनियरिंग	6.7	5.9	-0.8
6 आईपीसीएल	-65	5.8	70.8
7 एचटीएल	-3.1	-0.2	2.9
8 हिंदुस्तान जिंक	3.7	5.9	2.2
9 मॉडल फूड इंडिया	-2.1	-9.8	-7.7
10 पारादीप फास्फेट	-6.6	1.8	8.4
11 टाटा कम्यूनिकेशंस	13.7	11.1	-2.6
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	-3.24	0.65	3.89
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	-2.03	-13.4	-11.37
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	-1.21	14.05	DiD= 15.26

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

vii) *विक्रय वृद्धि*: औसतन, निजीकृत फर्मों के विक्रय वृद्धि दर पूर्व निजीकरण अवधि की तुलना में निजीकरण पश्चात् अवधि में 14.7 प्रतिशत से बढ़कर 22.3 प्रतिशत हो चुकी है। (तालिका 8) डिफ्रेंस-इन-डिफ्रेंस विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण किए जाने के कारण विक्रय वृद्धि में 4.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

viii) *प्रति कर्मचारी सकल लाभ*: चित्र 2 में दिखाया गया है कि औसतन, फर्मों के दोनों समूहों में, कर्मचारियों

की संख्या में कमी हुई है, किंतु समकक्ष फर्मों की तुलना में अन्य फर्मों में, इस कमी का परिमाण कुछ कम है। प्रति कर्मचारी सकल लाभ का आकलन चयनित 11 सीपीएसई फर्मों में से केवल 8 फर्मों का किया गया है, क्योंकि इनका डाटा ही उपलब्ध था। डिफ्रेंस इन डिफ्रेंस विश्लेषण से पता चलता है कि निजीकरण के कारण प्रतिकर्मचारी 21.34 लाख रुपये की वृद्धि सकल लाभ में हुई है। (तालिका 9)

तालिका 8: विक्रय वृद्धि वर्ष दर वर्ष ( प्रतिशत में )

निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	7.87	22.25	14.38
2 सीएमसी	20.19	4.66	-15.53
3 मारुति	20.26	16.18	-4.08
4 जेसोप	-2.45	17.26	19.71
5 लगान इंजीनियरिंग	0.22	17.05	16.83
6 आईपीसीएल	14.33	23.90	9.58
7 एचटीएल	19.29	82.10	62.81
8 हिंदुस्तान जिंक	10.44	28.34	17.90
9 मॉडल फूड इंडिया	18.36	4.02	-14.34
10 पारादीप फास्फेट	6.41	32.39	25.99
11 टाटा कम्प्यूनिक्शंस	46.58	-2.94	-49.52
12 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	14.68	22.29	7.61
13 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	59.37	62.09	2.72
14 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	-44.69	-39.80	<b>DiD = 4.89</b>

तालिका 9: सकल लाभ/कर्मचारी ( लाख रूपये में )

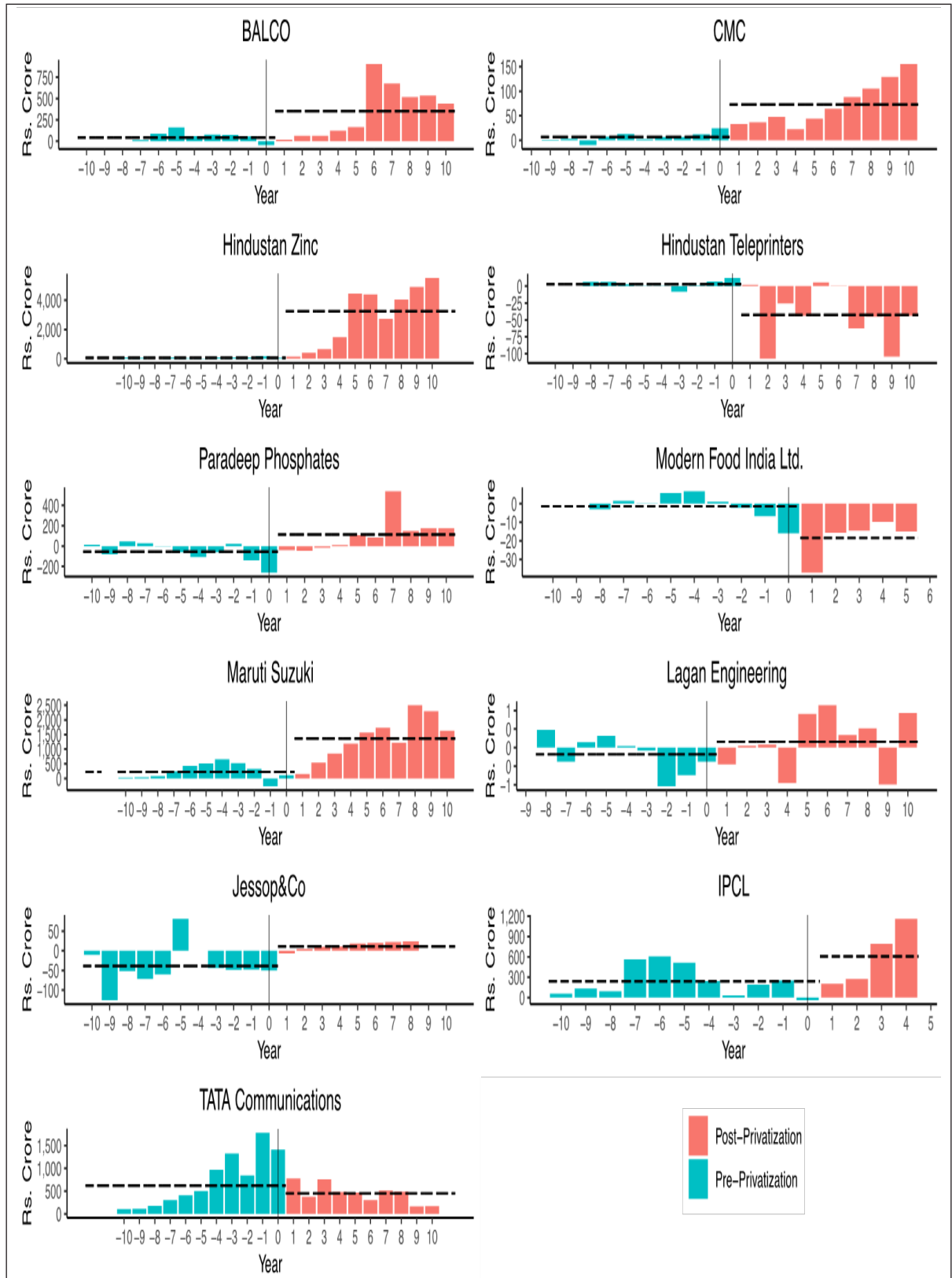
निजी सीपीएसई का नाम	पूर्व औसत	पश्चात औसत	पश्चात् में पूर्व को घटाने के बाद
1 बाल्को	0.46	10.87	10.42
2 सीएमसी	0.17	1.49	1.32
3 मारुति	4.75	21.01	16.26
4 जेसोप	-1.06	0.77	1.82
5 आईपीसीएल	1.89	4.14	2.26
6 हिंदुस्तान जिंक	0.26	166.66	166.40
7 पारादीप फास्फेट	-6.02	-14.96	-8.94
8 टाटा कम्प्यूनिक्शंस	22.28	13.42	-8.85
9 सभी निजीकृत फर्मों का संयुक्त औसत	2.84	25.43	22.58
10 समकक्ष फर्मों का संयुक्त औसत	0.54	1.78	1.24
11 निजीकृत फर्मों में से समकक्ष फर्मों को घटाकर	2.30	23.65	<b>DiD = 21.34</b>

स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

9.7 सर्वेक्षण में प्रत्येक व्यक्तिगत सीपीएसई के निष्पादन में बदलाव का जांच करेगा। चित्र 3 से 10 में दस वर्ष के पहले प्रमुख फर्म और रणनीतिक विनिवेश/निजीकरण के बाद मुख्य वित्तीय संकेतकों से होने वाले संचलन को दर्शाता हैं। व्यक्तिगत रूप से, प्रत्येक निजीकृत सीपीएसई

ने कुल कीमत, निवल लाभ, सकल राजस्व, निवल राजस्व अन्तर निजीकरण के बाद की अवधि बनाम निजीकरण से पहले की अवधि में बिक्री वृद्धि को दर्शाता है (हिन्दुस्तान टेलीप्रिन्टर, एम एफ आई एल और कुछ संकेतकों के मामले में घटा कम्प्युनिकेशन के सिवाय)

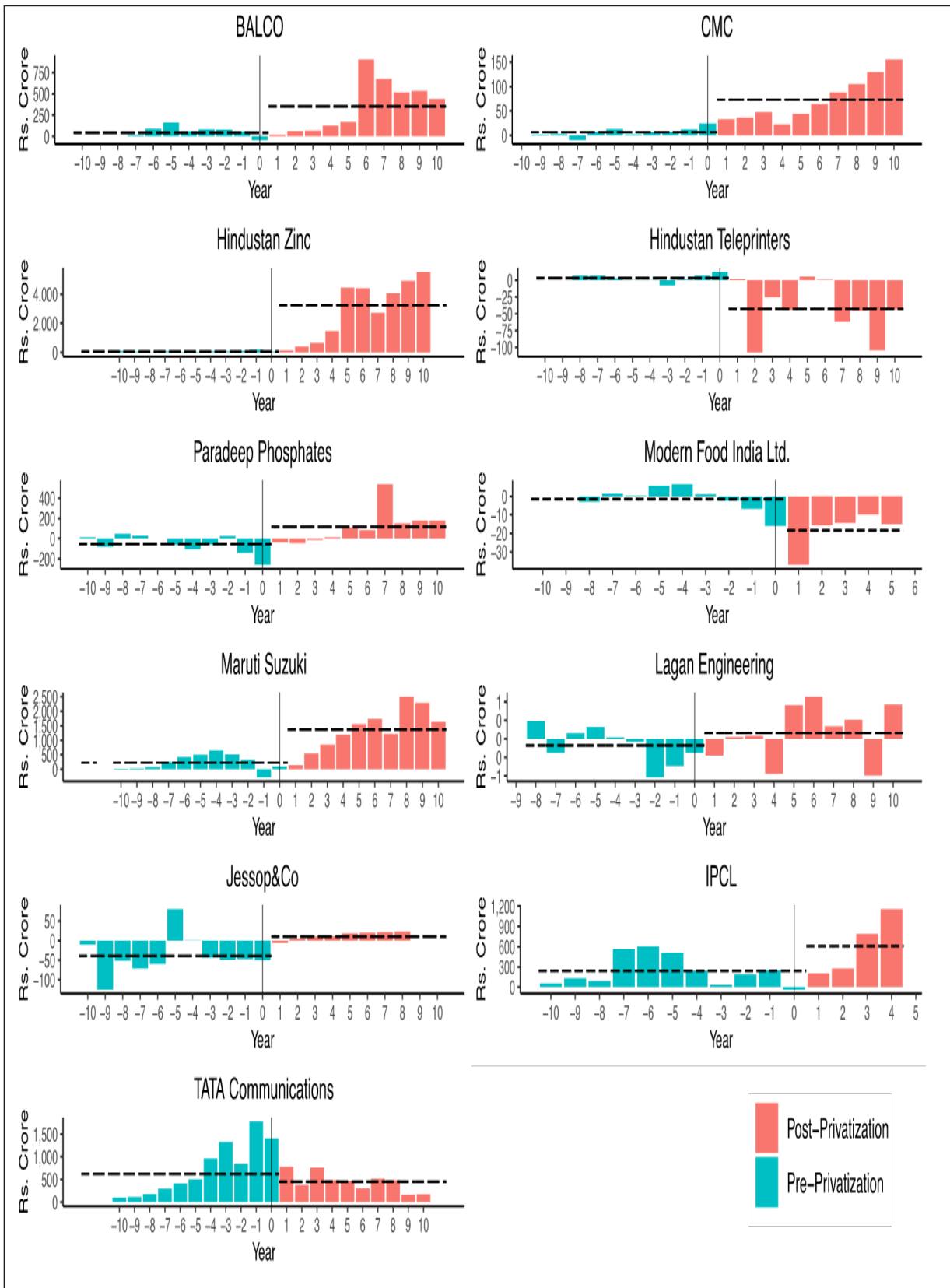
चित्र 3: निजी फर्मों का कुल मूल्य (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

चित्र 4: निजी फर्मों का कुल लाभ (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)

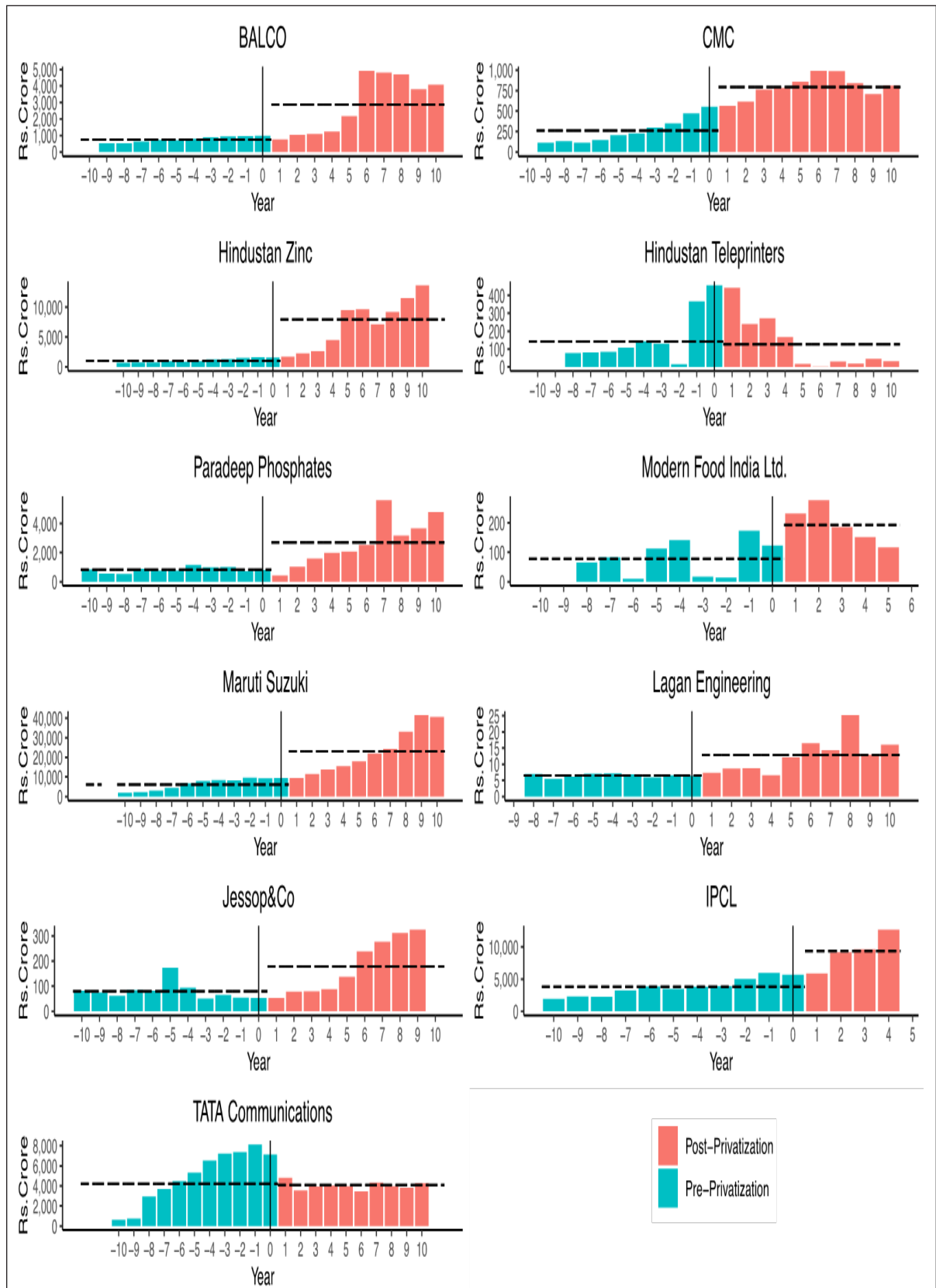


स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष



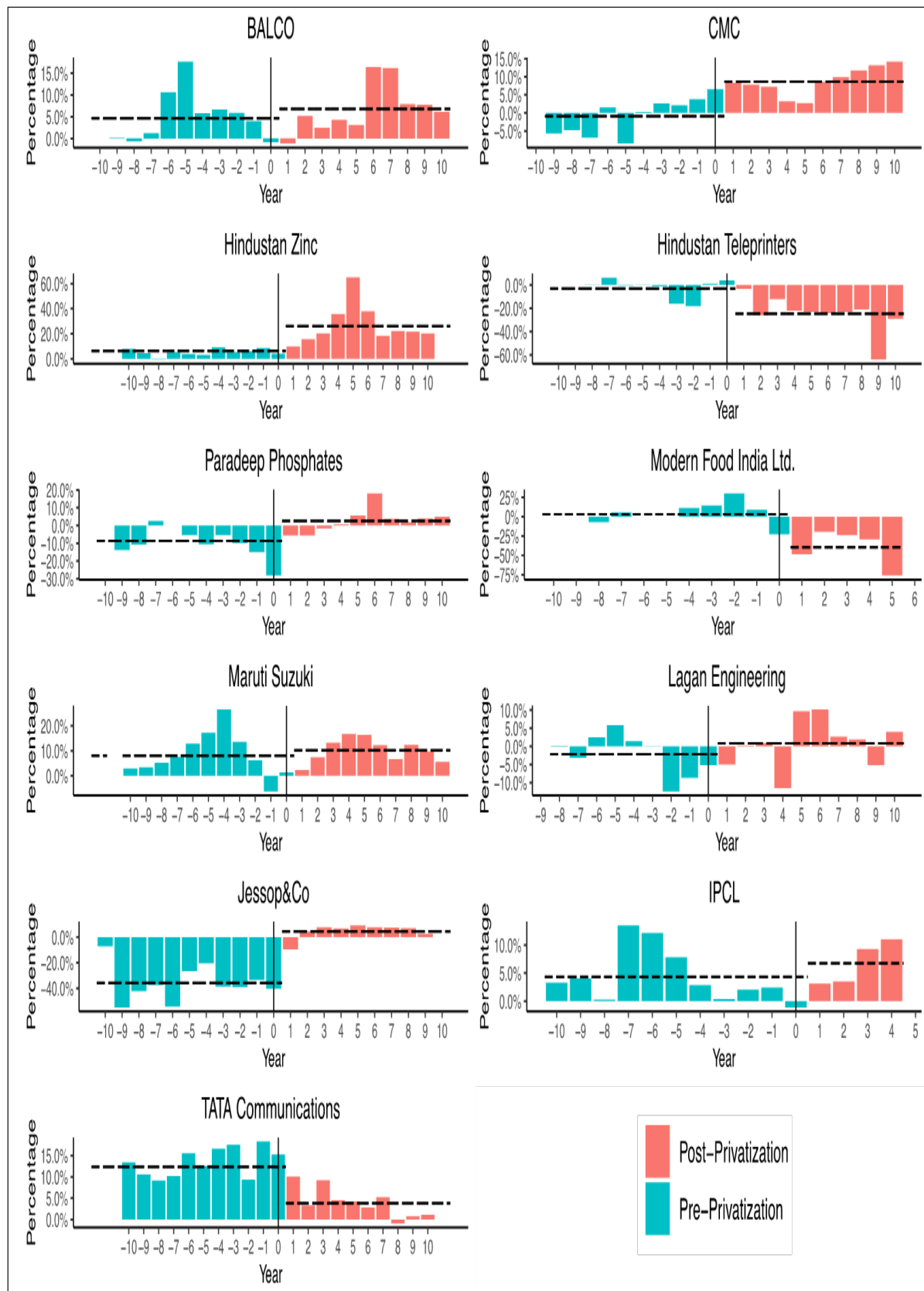
चित्र 5: निजी फर्मों का कुल राजस्व (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

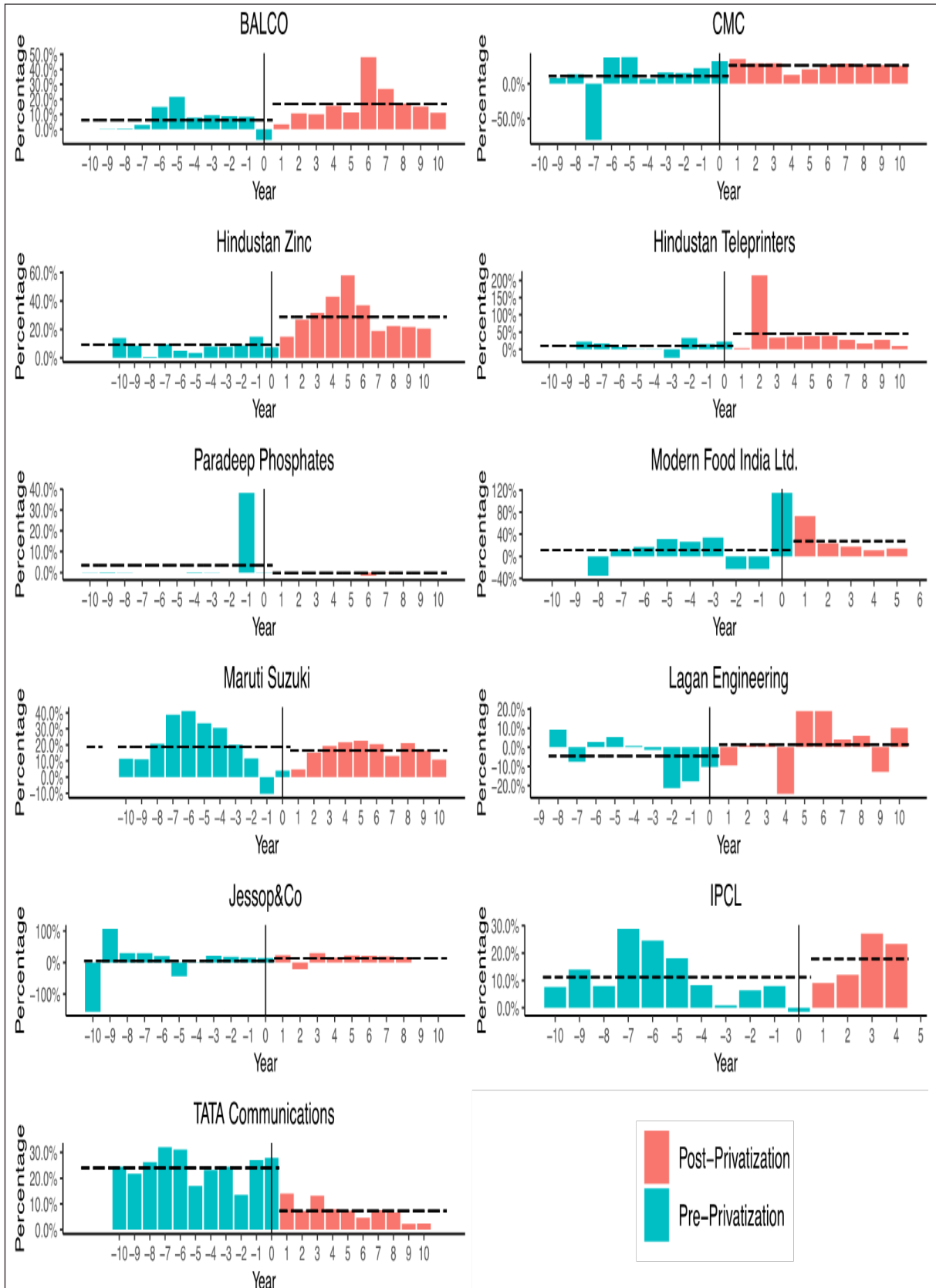
चित्र 6: निजी फर्मों के परिसंपत्तियों की वसूली (आरओए) (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

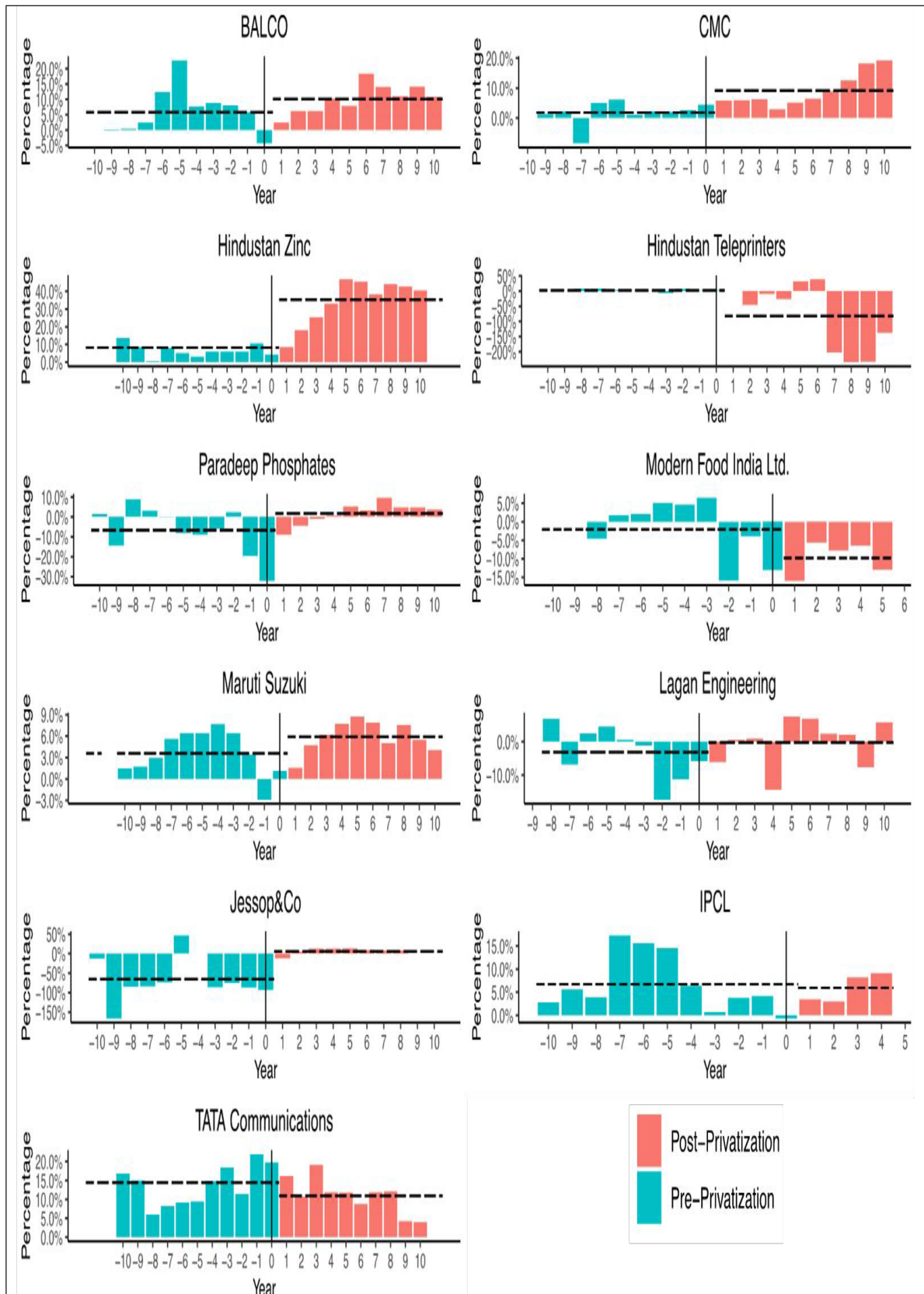
चित्र 7: निजी फर्मों के इक्विटी पर वसूली (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

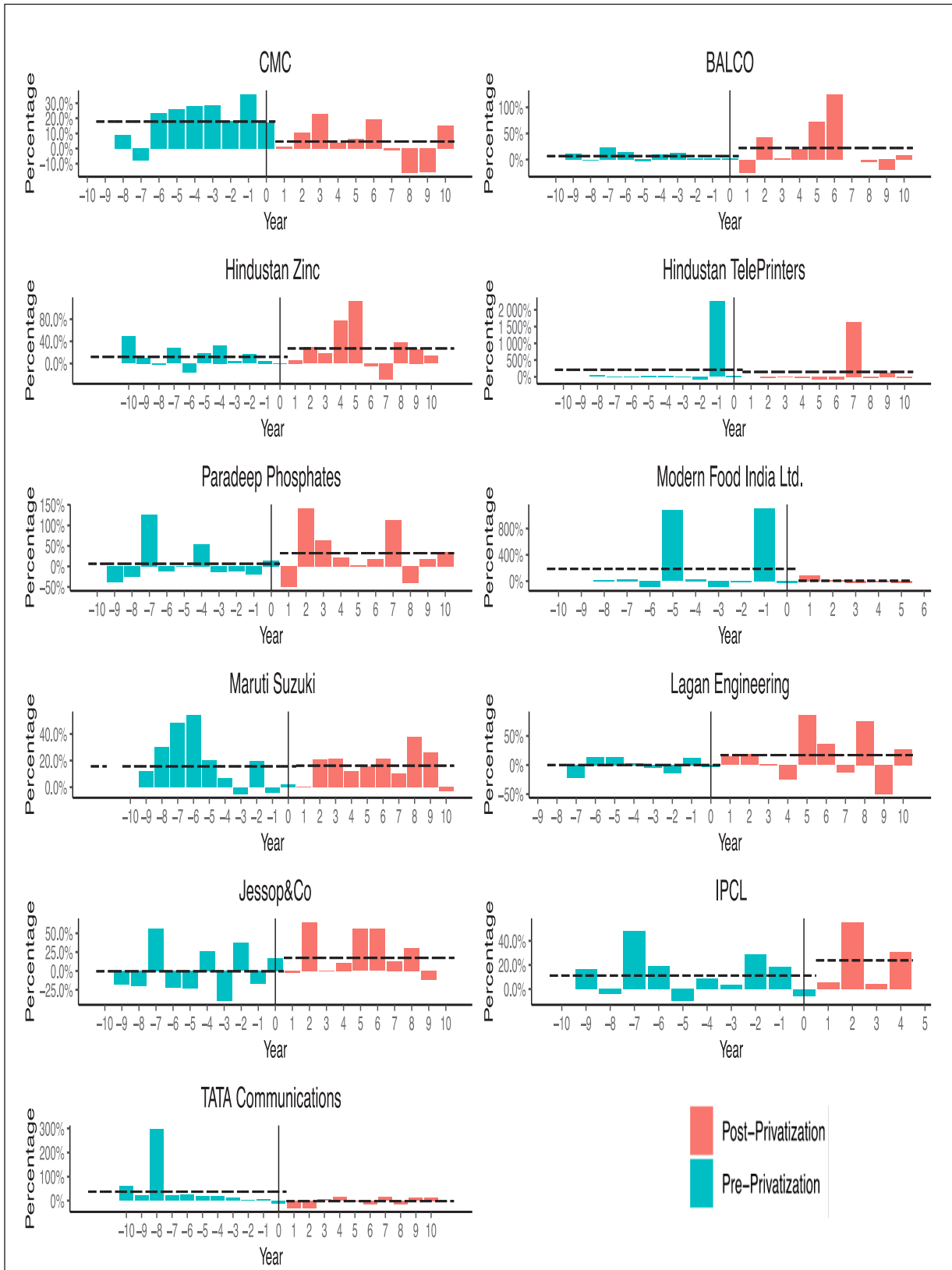
चित्र 8: निजी फर्मों का कुल लाभ मार्जिन (पूर्व पश्चात निजीकरण)



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

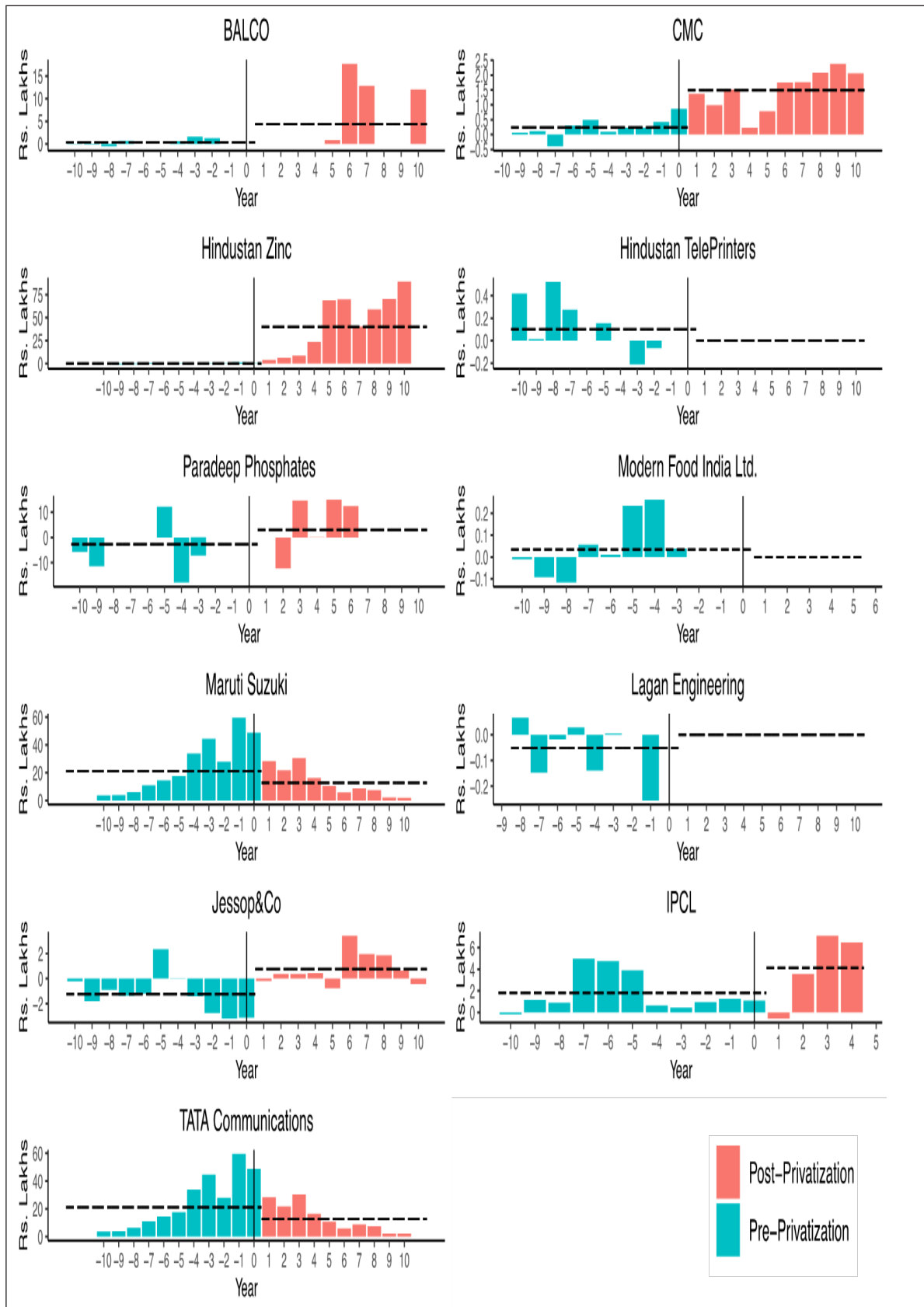
चित्र 9: निजी फर्मों का बिक्री ग्रोथ रेट ( पूर्व एवं पश्चात निजीकरण )



स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

चित्र 10: निजी फर्मों के प्रति कर्मचारी का सकल लाभ (पूर्व एवं पश्चात निजीकरण)



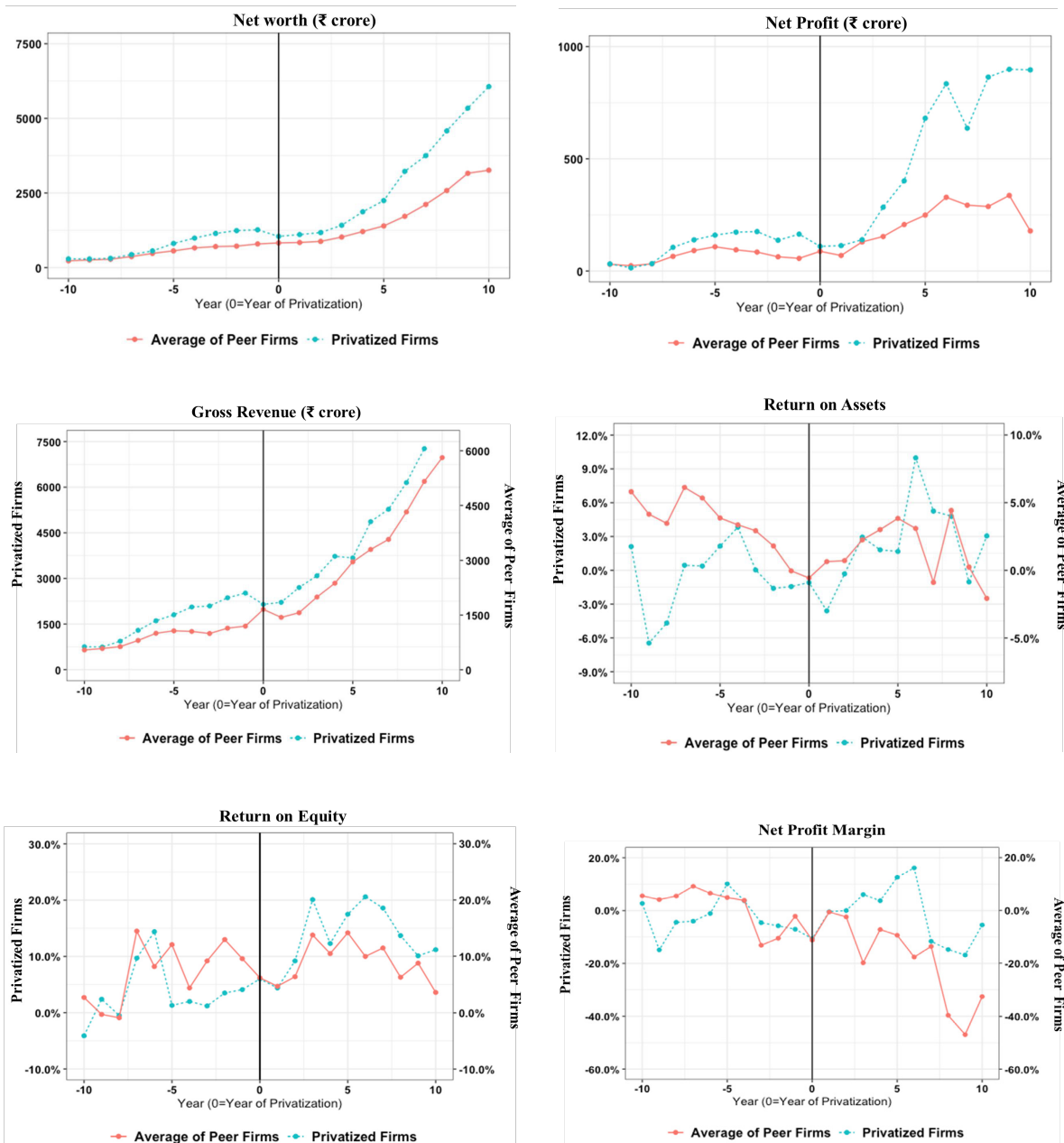
स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

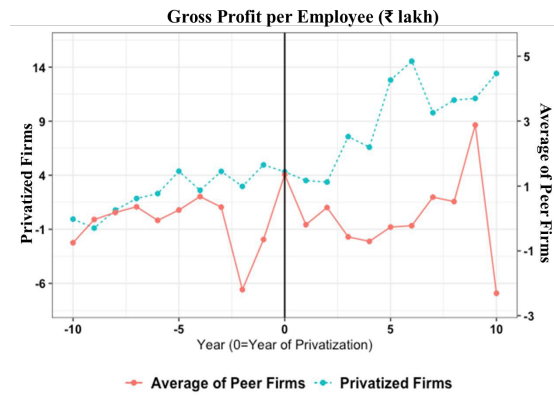
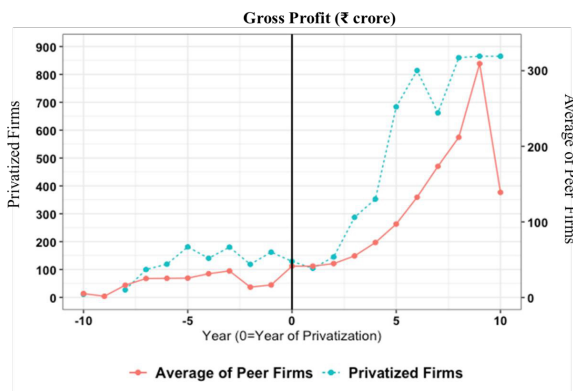
टिप्पणी: 0 = निजीकरण का वर्ष

9.8 चित्र 10 नीचे निजी सीपीएसई के निष्पादन के रुझान को दर्शाता है। विशिष्ट सीपीएसई के निजीकरण के पूर्व और पश्चात के 10 वर्षों के समय के उनके सहयोगियों की तुलना में औसत है। इस रुझान से हमें

निजीकरण के बाद निजी संस्थाओं के निष्पादन में यदि इनकी अपने सहयोगी फर्मों से तुलना की जाए तो परिवर्तन के पहलुओं को समझने में आसानी होती है।

चित्र 11: निजी फर्मों बनाम सहयोगी फर्मों के निष्पादन





स्रोत: सर्वेक्षण का परिकल सीएमआईई प्रोवेस से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर किया गया है।

## भावी परिदृश्य

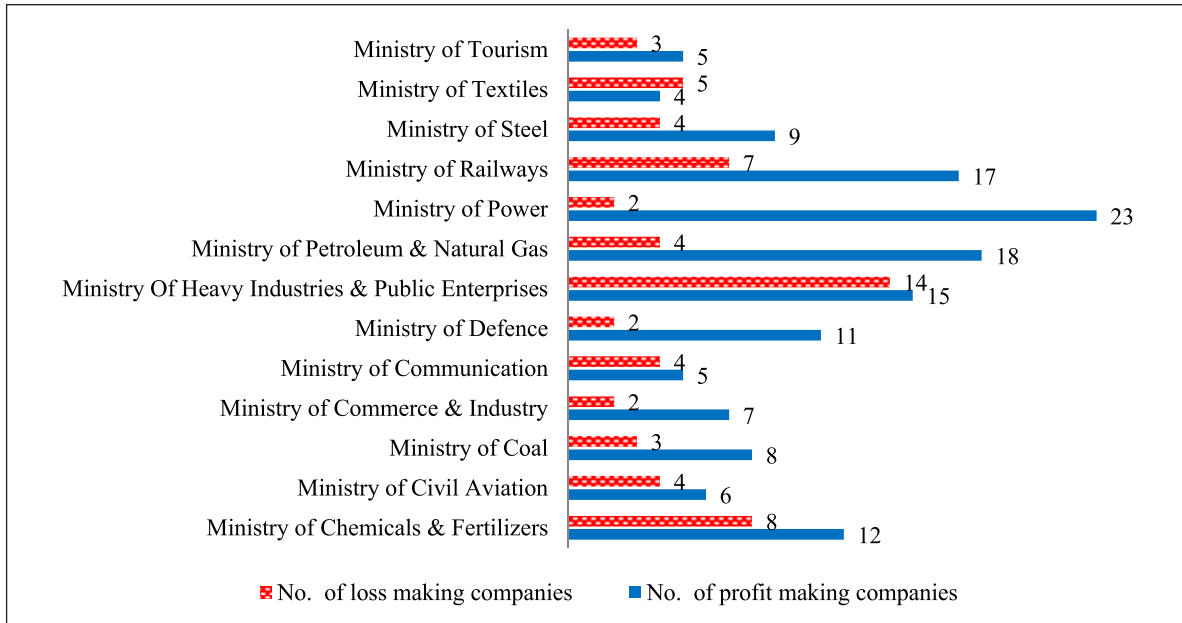
9.9 इस अध्याय में हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह पुष्टि करता है कि सीपीएसईएस की रणनीतिक बिक्री के माध्यम से विनिवेश फर्म के प्रदर्शन और समग्र उत्पादकता में सुधार करता है, और धन सृजन के लिए अपनी संभावना को अनलॉक करता है जिसका अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों पर गुणात्मक प्रभाव पड़ता है। रणनीतिक बिक्री के मार्ग के माध्यम से अत्यधिक विनिवेश के संदर्भ में “आसानी से हासिल किए जाने वाले लक्ष्य” का उपयोग संभावित उच्च लाभ लाने में, दक्षता को बढ़ावा देने प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और चयनात्मक सीपीएसईएस में प्रबंधन में व्यावसायवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए। रणनीतिक विनिवेश का ध्यान गैर-रणनीतिक व्यापार से हटाए जाने और पहचाने गए सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम में दक्षता और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देकर आर्थिक क्षमता का इष्टतम उपयोग किए जाने की आवश्यकता है। इसके बाद, अन्य जगहों पर, विशेष रूप से सार्वजनिक बुनियादी ढांचे जैसे सड़क, बिजली पारेषण लाइन, सीवेज प्रणाली, सिंचाई प्रणाली, रेलवे और शहरी बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए पूंजी को अनलॉक करेगा। यह उत्साहजनक है कि डीआईपीएम द्वारा समर्थकारी प्रावधान पहले से ही लागू किए गए हैं। मंत्रिमंडल ने विभिन्न सीपीएसई (अध्ययन के अनुबंध में यथा विस्तृत) में विनिवेश को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। राजकोषीय गुंजाइश के सृजन

को सुविधाजनक बनाने और सार्वजनिक संसाधनों के कुशल आवंटन में सुधार लाने के लिए इन पर ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है।

9.10 38 विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के तहत 264 सीपीएसई हैं। इनमें से 13 मंत्रालयों/विभागों के अधिकार क्षेत्र में लगभग 10 सीपीएसई है। चित्र 11 से ज्ञात हो रहा है कि अनेक सीपीएसई लाभ की स्थिति में है। हालांकि सामान्यतः बाजार में सीपीएसई ने कमजोर प्रदर्शन किया है तथा यह 2014-2019 की अवधि के दौरान ज्ञात हुआ कि सीएसई सीपीएसई इंडेक्स का औसत रिटर्न केवल 4 प्रतिशत था जबकि बीएसई का सूचकांक का रिटर्न 38 प्रतिशत था। विनिवेश कार्यक्रम का किसी भी तरह का निजीकरण करने का मुख्य उद्देश्य सरकारी इक्विटी स्टैक वैल्यू को अधिक बढ़ाना है। इस संदर्भ (बॉक्स 4) के लिए तेमासेक होल्डींग कम्पनी के अनुभवों से सीखना लाभदायक होगा। सरकार सूचीबद्ध सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी एक अलग कॉर्पोरेट इकाई को हस्तांतरित कर सकती है (चित्र 12)। इस इकाई का प्रबंधन एक स्वतंत्र बोर्ड द्वारा किया जाएगा। और समय-समय पर इन सीपीएसई में सरकारी हिस्सेदारी के विनिवेश के लिए अनिवार्य किया जाएगा। यह विनिवेश कार्यक्रम को व्यवसायिकता और स्वायत्तता प्रदान करेगा, जो बदले में सीपीएसई के आर्थिक प्रदर्शन में सुधार करेगा।

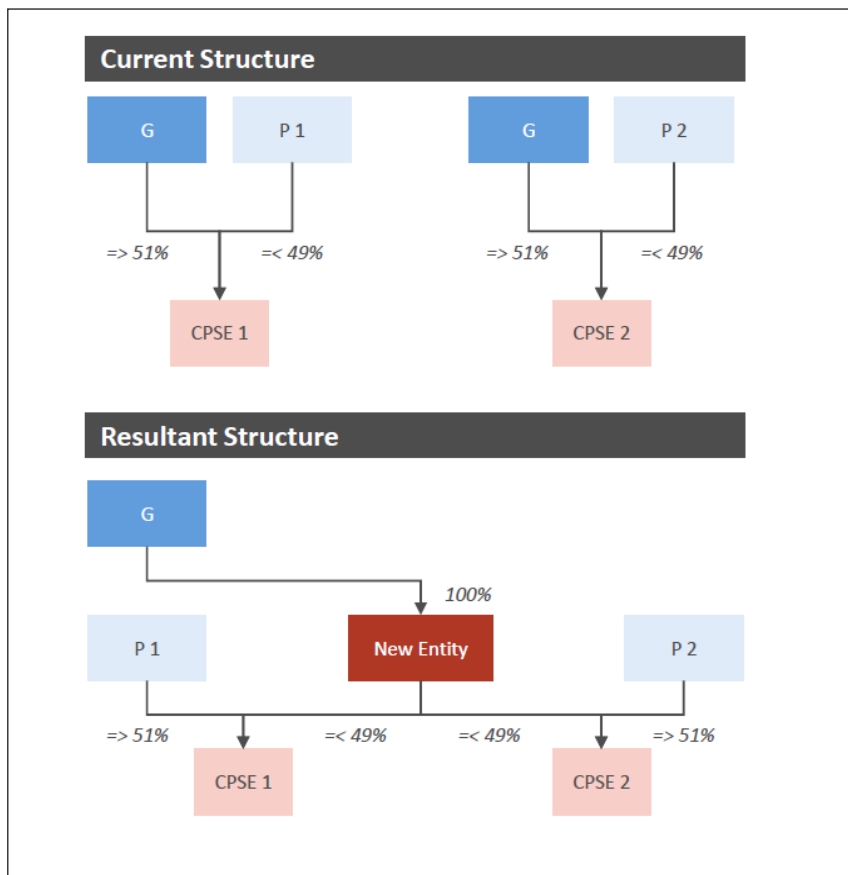


चित्र 11: विभिन्न मंत्रालयों के अधीन लाभकारी सीपीएसई की संख्या



स्रोत: लोक उद्यम विभाग

चित्र 12: विनिवेश निगमीकरण हेतु प्रस्तावित संरचना



#### बॉक्स 4: टेमारोक होल्डिंग्स लिमिटेड- सिंगापुर का निजीरिण मॉडल

25 जून 1974 को सिंगापुर सरकार द्वारा एक निजी वाणिज्यिक सत्व के रूप में इसकी सरकारी-संबद्ध कम्पनियों (जी.एल.सी.) में इसकी निवेश को धारण कर प्रबंधित करने के लिए टेमासे का होल्डिंग्स को निगमित किया गया था। टेमासेक होल्डिंग्स वित्त मंत्रालय के स्वामित्व में है और जो सिंगापुर कम्पनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रचालित होता है। टेमासेक बोर्ड के 13 सदस्य हैं जिनमें से अधिकांश सदस्य निजी क्षेत्र के गैर-कार्यकारी और स्वतंत्र व्यावसायिक नेता हैं। तन से इस कम्पनी ने दूरसंचार, मीडिया, वित्तीय सेवा, ऊर्जा, आधारिक संरचना, इंजीनियरी, फार्मास्युटिकल्स और जीव-विज्ञान जैसे क्षेत्रों में व्यवसाय के मुख्य क्षेत्रों को कबर करने के लिए अपने प्रचालन में विस्तार किया है।

टेमासेक ने ऐसे कई मूल निवेशों का प्रबंधन किया है, जिनमें शिपिंग फर्म्स (एन.ओ.एल. कम्पल, सेम्बावंग), एक बैंक (डी.बी.एस. बैंक) और सिस्टम्स इंजीनियरी-समूह (सिंगापुर टेक्नोलॉजी, सिंगापुर टेलीकॉम) जैसी राष्ट्रीय सम्पत्तियां सम्मिलित हैं। टेमासेक ने इन सभी जी.एल.सी. में इनके मूल स्टेक्स को सम्मिलित करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण निवेश को बरकरार रखा है। मार्च 2002 से, टेमासेक ने सिंगापुर से बाहर अपने पोर्टफोलियो को चित्रित करना प्रारंभ कर दिया था ऐसा है कि इसके निवेश का एक तिहाई हिस्सा विकसित बाजारों का है, एक तिहाई हिस्सा विकासशील देशों और एक तिहाई हिस्सा सिंगापुर का है। विदेशी कम्पनियों में कम्पनी के कुद प्रमुख निवेशों में स्टैंडर्ड चार्टर्ड, आइ.सी.आई.सी.आई. बैंक (भारत), बैंक, एस.एम.आर.टी., एस.टी.इंजीनियरिंग, मीडियाकॉर्प और सिंगापुर पॉवर शामिल है।

31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार यह 230 बिलियन यू.एस. डॉलर से अधिक निवल पोर्टफोलियो का प्रबंध करता है। 1974 के आरम्भ से, इसका चक्रवृद्धि वार्षिक कुल शेयरहोलडर प्रतिफल सिंगापुर डॉलर में 15 प्रतिशत है।

#### अध्याय एक नजर में

- भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) में 53.29 प्रतिशत की सरकार शेयरधारिता के रणनीतिक विनिवेश के अनुमोदन से एचपीसीएल की तुलना में बीपीसीएल के शेयरधारकों के इक्विटी मूल्य में लगभग 33,000 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई। इसकी परिणति बीपीसीएल के समग्र फर्म मूल्य में एक स्पष्ट वृद्धि के रूप में हुई, और इससे राष्ट्रीय संपदा में इतनी ही राशि तक की बढ़ोतरी हुई।
- वर्ष 1999-2000 से 2003-04 तक किए गए रणनीतिक निवेश से 11 केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निष्पादन से पहले-बाद के तुलनात्मक विश्लेषण से यह पता चलता है कि समकक्ष फर्मों की तुलना में निजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के निवल मूल्य, निवल लाभ और आस्तियों के प्रतिफल (आरओए) में निजीकरण की अवधि के बाद, औसतन, उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह बेहतर निष्पादन प्रत्येक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम के लिए व्यक्तिगत रूप से भी सच बैठता है। आस्तियों का प्रतिफल समकक्ष फर्मों को पीदे छोड़ते हुए ऋणात्मक से लगभग धनात्मक हो गया है जो यह संकेत देता है कि निजीकृत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अपने संसाधनों का और अधिक उत्पादक रूप से उपयोग करने में समर्थ रहे हैं। कर्मचारियों की उत्पादकता भी बढ़ी है, क्योंकि सभी प्रति कर्मचारी अंतर, जैसेकि प्रति कर्मचारी निवल लाभ, प्रति कर्मचारी सकल राजस्व और प्रति कर्मचारी निवल मूल्य में निजीकरण के बाद की अवधि में बढ़ोतरी हुई है।
- हमारा विश्लेषण स्पष्ट रूप से यह अभिपुष्टि करता है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की रणनीतिक बिक्री के जरिए विनिवेश निवल मूल्य, लाभपरकता, बिक्री में वृद्धि, इसके शेयरधारकों के लिए दक्षता और प्रतिफल की दृष्टि से बेहतर निष्पादन के फलस्वरूप संपदा सृजित करने के लिए इन उद्यमों की संभावना के द्वारा खोल देता है।
- रणनीतिक बिक्री के मार्ग के जरिए अत्यधिक विनिवेश की दृष्टि से 'आसानी से हासिल किए जाने वाले लक्ष्यों' का उपयोग पहले से अधिक लाभपरकता, दक्षता संवर्धन, प्रतिस्पर्धात्मकता तथा ऐसे चुनिंदा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में व्यवसायवाद को बढ़ावा देने के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए मंत्रिमंडल ने सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

## संदर्भ

- Affuso, L., A. Angeriz, and M. Pollitt. 2009. "The impact of privatization on the efficiency of train operation in Britain". CGR Working Paper No. 28. Centre for Globalization Research School of Business and Management. Queen Mary University of London.
- Berkman, Henk, Rebel A. Cole, and Jiang Lawrence Fu. 2012. "Improving Corporate Governance Where the State is the Controlling Block Holder: Evidence from China". *SSRN Electronic Journal*.
- Borisova, Ginka, and William L. Megginson. 2011. "Does Government Ownership affect the Cost of Debt? Evidence from Privatization". *Review of Financial Studies* 24 (8): 2693-2737.
- Boubakri, Narjess, Sadok El Ghouli, Omrane Guedhami, and William L. Megginson. 2018. "The Market Value of Government Ownership". *Journal of Corporate Finance* 50: 44-65.
- Brown, David J., John S. Earle, and Almos Telegdy. 2015. "Where Does Privatization Work? Understanding The Heterogeneity in Estimated Firm Performance Effects". *Journal of Corporate Finance* 41: 329-362.
- Brown, J. David, John S. Earle, and Almos Telegdy. 2006. "The Productivity Effects of Privatization: Longitudinal Estimates from Hungary, Romania, Russia, And Ukraine". *Journal of Political Economy* 114 (1): 61-99.
- Chen, Gongmeng, Michael Firth, Yu Xin, and Liping Xu. 2008. "Control Transfers, Privatization, And Corporate Performance: Efficiency Gains in China's Listed Companies". *Journal of Financial and Quantitative Analysis* 43 (1): 161-190.
- Choi, Seung-Doo, Inmoo Lee, and William Megginson. 2010. "Do Privatization IPOs Outperform in The Long Run?". *Financial Management* 39 (1): 153-185.
- Conway, Paul, and Richard Herd. 2009. "How Competitive Is Product Market Regulation in India?". *OECD Journal: Economic Studies* 2009 (1): 1-25.
- Dinc, I. Serdar, and Nandini Gupta. 2011. "The Decision to Privatize: Finance and Politics". *The Journal of Finance* 66 (1): 241-269.
- Florio, Massimo. *The great divestiture: Evaluating the welfare impact of the British privatizations, 1979-1997*. MIT press. 2004.
- Gan, Jie, Yan Guo, and Chenggang Xu. 2014. "Decentralized Privatization and Change of Control Rights in China". *The Review of Financial Studies* 31 (10): 3854-3894.
- Ghosh, Saibal. 2011. "R&D in Public Enterprises". *Science, Technology and Society* 16 (2): 177-190.
- Gupta, Nandini. 2005. "Partial Privatization and Firm Performance". *The Journal of Finance* 60 (2): 987-1015.
- Li, Bo, William L. Megginson, Zhe Shen, and Qian Sun. 2016. "Do Share Issue Privatizations Really Improve Firm Performance in China?". *SSRN Electronic Journal*.
- Makhija, Anil K. "Privatization in India." *Economic and Political Weekly* 41, no. 20 (2006): 1947-951.

- Meggison, William L, and Jeffrey M Netter. 2001. "From State to Market: A Survey of Empirical Studies On Privatization". *Journal of Economic Literature* 39 (2): 321-389.
- Meggison, William L. 2007. "Introduction to The Special Issue On Privatization". *International Review of Financial Analysis* 16 (4): 301-303.
- Meggison, William L. 2017. "Privatization, State Capitalism, And State Ownership of Business in The 21St Century". *Foundations and Trends® In Finance* 11 (1-2): 1-153.
- Meggison, William L., Robert C. Nash, Jeffrey M. Netter, and Annette B. POULSEN. 2004. "The Choice of Private Versus Public Capital Markets: Evidence from Privatizations". *The Journal of Finance* 59 (6): 2835-2870.
- Meggison, William. 2010. "Privatization and Finance". *Annual Review of Financial Economics* 2 (1): 145-174.
- Meher, Kishor & Samiran, Jana. (2012). Bottom line of Divested PSE's in Post Privatization Scenario. 4D *International Journal of Management & Science*. III.
- Ministry of Finance, Department of Disinvestment, Government of India. 2007. Dipam.Gov.In. [https://dipam.gov.in/sites/default/files/white\\_paper.pdf](https://dipam.gov.in/sites/default/files/white_paper.pdf).
- Muhlenkamp, Holger. 2013. "From state to market revisited: a reassessment of the empirical evidence on the efficiency of public (and privately-owned) enterprises". *Annals of Public and Cooperative Economics* 86 (4): 535-557.
- OECD. 2008. "Improving Product Market Regulation in India". OECD Economics Department Working Papers.
- O'Toole, Conor M., Edgar L.W. Morgenroth, and Thuy T. Ha. 2016. "Investment Efficiency, State-Owned Enterprises and Privatization: Evidence from Viet Nam in Transition". *Journal of Corporate Finance* 37: 93-108.
- Oum, Tae H., Nicole Adler, and Chunyan Yu. 2006. "Privatization, Corporatization, Ownership Forms and Their Effects On the Performance of the World's Major Airports". *Journal of Air Transport Management* 12 (3): 109-121.
- Parker, David. 2004. "The UK's Privatization Experiment: The Passage of Time Permits A Sober Assessment". Cesifo Working Paper No. 1126.
- Stiglitz, Joseph E. *Privatization: Successes and Failures*. Edited by Roland Gerard. Columbia University Press, 2008.
- Subramanian, Krishnamurthy, and William L. Meggison. 2018. "Employment Protection Laws and Privatization". *SSRN Electronic Journal*.
- Tran, Ngo My, Walter Nonneman, and Ann Jorissen. 2015. "Privatization of Vietnamese Firms and Its Effects On Firm Performance". *Asian Economic and Financial Review* 5 (2): 202-217.
- Wolf, Christian O. H., and Michael G. Pollitt. 2008. "Privatizing National Oil Companies: Assessing The Impact On Firm Performance". *SSRN Electronic Journal*.

सीपीएसई की सूची जो आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) की 'सैद्धांतिक रूप से' स्वीकृति प्राप्त कर चुकी है

क्रम सं.	सीपीसीई का नाम	सीसीईए अनुमोदन की तारीख
<b>सतत्</b>		
1	एनएमडीसी का नगरनार स्टील प्लांट (एनएसपी)	27.10.2016
2	सेल की तीन यूनितें: वीआईएसपी, भद्रावती, एसएसपी, सलेक एवं एएसपी, दुर्गापुर	27.10.2016
3	फेरा स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल)	27.10.2016
4	सेंट्रल ईलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड (सीईएल)	27.10.2016
5	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बीईएमएल)	27.10.2016
6	सीमेंट कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआईएल) का नयागांव यूनित	27.10.2016
7	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (आई) लिमिटेड (बी एंड आर)	27.10.2016
8	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडया) लिमिटेड (ईपीआईएल)	27.10.2016
9	स्कूटर इंडिया लिमिटेड (एसआईएल)	27.10.2016
10	भारत पम्पस एंड कंप्रेसर लिमिटेड (बीपीसीएल)	27.10.2016
11	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड (एचएनएल)	27.10.2016
12	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बनस लिमिटेड (एचएफएल)	27.10.2016
13	पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल)	27.10.2016
14	प्रोजेक्ट डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड (पीडीआईएल)	27.10.2016
15	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड (एचपीएल)	27.10.2016
16	हिंदुस्तान एंटी बायोटेक्स लिमिटेड (फार्मास्यूटिकल्स विभाग)	28.12.2016
17	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (फार्मास्यूटिकल्स विभाग)	28.12.2016
17	एयर इंडिया और इसकी सहायक कंपनियां	28.06.2017
19	इंडिया मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल्स कोरपोरेशन लिमिटेड (आईएमपीसीएल)	01.11.2017
20	कर्नाटक एंटी बायोटेक्स फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (केएपीएल)	01.11.2017
21	एचएलएललाइफ केयर लिमिटेड (एचएलएल)	01.11.2017
22	कामराज पोर्ट लिमिटेड (केपीएल)	28.02.2019
23	शिपिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया (एससीआई)	20.11.2019
24	भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	20.11.2019
25	कंटेनर कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कोनकोर)	20.11.2019
26	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड (टीएचडीसीआईएल)	20.11.2019
27	नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कोरपोरेशन लिमिटेड (निपको)	20.11.2019
28	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (एनआईएनएल)	08.01.2020
<b>लेन-देन हुआ</b>		
29	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल)	19.07.2017
30	ग्रामीण विद्युतीकरण कोरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी)	06.12.2018
31	हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कोरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी)	27.10.2016
32	नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी)	27.10.2016
33	ड्रेजिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल)	01.11.2017

टिप्पणी: सरकार ने पिछले दो वर्षों में कार्यान्वित उपाय के तहत पहले ही हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोरपोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) (इंडियन ऑयल कोरपोरेशन लिमिटेड/आईओसी को), ग्रामीण विद्युतीकरण कोरपोरेशन लिमिटेड (आरईसी) (पावर फाइनेंस कोरपोरेशन/पीएफसी को), ड्रेजिंग कोरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (डीसीआईएल) (चार पोर्टों के एक कंसोर्टियम को), हॉस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कोरपोरेशन लिमिटेड (एचएससीसी) (एनबीसीसी को) और नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कोरपोरेशन लिमिटेड (एनपीसीसी) (डब्ल्यूएपीसीओएस को) जैसे 5 सीपीएसई में अपनी हिस्सेदारी बेचकर रुपये 52,869 करोड़ राशियां प्राप्त की है।

स्रोत: निवेश और सार्वजनिक सम्पदा प्रबंधन विभाग (डीआईपीएम) और प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी)